Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That the Bill, as amended, be passed."

The motion was adopted.

12.33 hrs.

MOTION *RE*. APPOINTMENT OF COMMITTEE FOR RESTRICTION OF INDIVIDUAL MONTHLY EXPENDITURE

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Lohia.

Dr. Ram Manohar Lohia *rose*—

Shri Shashi Ranjan (Pupri): I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Let him move the motion.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) मेरा इस में ऐतराज है। कि व्यवस्था का प्रश्न इस वक्त नहीं आ सकता है। उन को भाषण देने दीजिये, प्रस्ताव रखने दीजिये, तब आ सकता है।

Shri Shashi Ranjan: The No-Day-Yet-Named Motion is moved under Chapter XIV of the Rules of Procedure, which governs all the motions. There are specific rules......

Mr. Deputy-Speaker: That is true. Let him move the motion first and then only a point of order will arise. At the outset how can a point of order arise? I suggest that he may move the motion first and then the hon. Member may raise his point of order.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में एक बार पहले तीन आने बनाम 15 आने की बहस हो चुकी है। वह पूर्वार्द्ध था। आज की बहस रोग का निदान है। वह रोग की बहस थी। यह बहस कि खर्चे पर सीमा लगा दी जाय और उस से बचे हुए रुपए से देश की उन्नति कराई जाये ......

Shri Shashi Ranjan: Is he moving..

Mr. Deputy-Speaker: Before moving the motion, he is entitled to make a speech. There is a provision for it. How can the hon. Member stop him?

Shri Shashi Ranjan: I rise on a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Let him move the motion. After the speech also, he can move.

Shri Shashi Ranjan: Let him first move the motion.

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बोल लूं तब मैं अपना प्रस्ताव आप के सामने रखूंगा और फिर उस के बाद जो कुछ हूंगा वह होगा। ....(व्यवधान)... अगर आप की आज्ञा हो जायगी तो बात अलग है। नहीं तो मुझे अपना भाषण करने दीजिए, तब मैं अपना प्रस्ताव रखूंगा।

Mr. Deputy-Speaker: He may move the motion first.

डा० राम मनोहर लोहिया : यह सभा संकल्प करती है कि सरकार को व्यक्तिगत मासिक व्यय 1500 रुपये तक सीमित करने के हेतु प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करनी चाहिये ताकि विकास कार्य में लगाने के लिए प्रति वर्ष एक हजार करोड़ रुपया उपलब्ध किया जा सके।.....

जैसा अध्यक्ष महोदय, मैं ने कहा ....

Shri Shashi Ranjan: I rise on a point of order......

Mr. Deputy-Speaker: As I have said, let him make his speech, and then I shall allow the hon. Member.

Shri Lobo Prabhu (Udipi): It is a very vital point of order. This motion is against the constitutional provisions relating to private property and income. This House should not make itself rediculous by discussing a motion like this, as long as the Constitution stands what it is. So,

my point of order is that the constitutional point must be explored before any time of the House is taken up on this motion.

श्री मधु लिमये : प्रापर्टी का कोई सवाल नहीं है, एक्सपेंडीचर का सवाल है।

Shri Shashi Ranjan: My askhelp is not that, but it is something else.

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): This is morally correct, socially correct and constitutionally correct.

Mr. Deputy-Speaker: Does this House have no right to consider the incomes policy, as I would call it? Whatever the motion be, it is a question relating to the incomes policy in this country. I have personally gone into this aspect, and the hon. Mover is perfectly within his rights. It does not contravene any provision of the Constitution. It is a motion regarding the incomes policy. That is all. We are not concerned with the figure that has been mentioned in the motion.

Dr. Sushila Nayar (Jhansi): Further, it does not say that there will be no property.

Shri Shashi Ranjan: I want to raise a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: Shri Lobo Prabhu had raised a constitutional objection and I had overruled it. He did not raise a point of order but a constituational objection as to whether we were competent to discuss the incomes policy. I have overruled that objection.

Shri Shashi Ranjan: My point of order is this. This no-day yet-named motion moved by Dr. Ram Manohar Lohia comes within chapter XIV of our Rules of Procedure which governs motions; there are certain specific rules for motions. One of the provisions is:

"In order that a motion may be admissible, it shall satisfy the folowing conditions, namely:—

All the conditions must be fulfilled, and no condition could be left out. There are two specific conditions which this motion does not satisfy. One is:

"It shall not revive discussion of a matter which has been discussed in the same session.

Dr. Ram Manohar Lohia, while speaking on the budget on the 7th June, 1967 had discussed this matter, and he had said:

"मुझे इस से मतलब नहीं कि खर्चे के ऊपर केवल सीमा कानून से लगाते हो या आयकर से लगाते हो या किस तरह से लगाते हो। लेकिन सीमा बांधो खर्चा करने के लिए जैसा भी हो। आज के हिन्दुस्तान में मैं पन्द्रह सौ रूपये से ज्यादा किसी को नहीं खर्च करने देना चाहता हूं जिस में वित्त मंत्री का तो पन्द्रह सौ भी नहीं पड़ेगा, बारह तेरह सौ शायद पड़ जाय और उसमें सुविधायें वगैरह शामिल हों। तो खर्च की अगर सीमा बांध दी जाए तो मेरे हिसाब से करीब हजार से पन्द्रह सौ करोड़ यानी 15 अरब रुपया साल बच सकता है। लोग इस हिसाब को सुन कर दंग रह जाते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है।" इत्यादि

This means that he had discussed this issue in this very session. So, under this rule, he cannot move a motion on the same matter during this same session.

Another provision which this motion does not satisfy is this:

"It shall be restricted to matter of recent occurrence; I do not think there is any matter of recent occurrence which this motion seeks to raise.

So, under these two conditions this motion cannot be moved. I want your ruling on this matter. Under these rules, this motion cannot be taken up as it has been presented before the House by my hon. friend.

Shri S. M. Banerjee *rose*—

Mr. Deputy-Speaker: We have only a limited time at our disposal. Let us concentrate on the motion itself. The objection that he has raised is not valid for two reasons. Firstly, there was no specific motion of this nature debated upon by this House.

Shri Shashi Ranjan: It should not revive a discussion which has already taken place.

Mr. Deputy-Speaker: Another thing is that either during the general budget discussion or during the discussion of any financial business that takes places in the House, every policy matter is discussed and debated. That does not preclude any member from bringing forward a positive Motion regarding incomes policy.

Therefore, let him continue.

डा० राम मनोहर लोहिया : (कन्नौज) : अध्यक्ष महोदय, तीन आना बनाम पन्द्रह आना वाली बहस पूर्वार्ध थी, पहले की बहस थी, आज की बहस 1500 रु० महीने की सीमा लगाने वाली उत्तरार्द्ध की बहस है, रोग का निदान है। यह कहते वक्त एक बात मैं साफ कर दूं—रुपये का मूल्य बदलता रहता है। अगर मुझे 6 महीने पहले बोलना होता या साल भर पहले मैं एक हजार रुपया कहता और मैं यह दावा करता हूं कि मेरा सुझाव यदि लागू कर दिया जाय तो यही 1500 रु० एक महीने के अन्दर अन्दर यानी सुझाव लागू होने के एक महीने के अन्दर अन्दर दो हजार रुपया कम से कम हो जायगा, यानी जो 100 रुपये है वह 125 हो जायगा। क्योंकि रुपये का मूल्य बदलता रहता है।

सब से पहले मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य कई बार पूछ बैठते हैं, यह हो कैसे ? बात तो बड़ी अच्छी है, तो मैं जड़ में जाना चाहता हूं। कैसे यह हो ? हम बहुत तरह के टैक्स लगाते हैं। एक लाख रुपए में से 92 हजार रुपया आय-कर ले लेते हैं, फिर भी नहीं हो पाया, दौलत के ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर भी नहीं हो पाया, यहां तक कि खर्चे पर भी टैक्स लगाया, फिर भी नहीं हो पाया। मैं उदाहरण के लिये, केवल उदाहरण के लिये एक बात कहना चाहता हूं—स्रोत पर जाओ, स्रोत कहां—जहां पर लोग खर्चा कर रहे हों, ऐसी तरकीबें निकालो कि उन विलासी खर्चों को रोक दिया जाय, जैसे कि मोटरवाली बात को लेता हूं। इस समय चार लाख निजी मोटरों का इस्तेमाल अपने देश में हो रहा है अगर मान लो कि एक मोटर पर औसतन 500 रु० महीने का खर्चा रखा जाय, कुछ 200—300 वाली हैं, कुछ हजार दो हजार वाली हैं, अगर सब को लेकर औसतन 500 रु० रखा जाय, तो करीब 200 करोड़ रुपये की बचत हो जाती है। थोड़ी देर के लिये मान लें कि आखिर चलना-फिरना तो होगा ही बसों से या टैक्सियों से, या मान लीजिए किसी संस्था या सरकारी गाड़ियों में, तो भी 200 करोड़ रुपये की बचत इन निजी मोटरों के बन्द कर देने से हो जायगी, स्रोत के ऊपर इस तरह से पहुंचा जा सकता है।

असल में मैं ने यह प्रश्न खाली इस लिये नहीं उठाया है कि हम को समाज के अन्दर कोई न्याय कायम करना है। सब से बड़ी बात यह है कि जब हम अभाव को कमी को, जब तक हम अपने यहां जो अभाव है, तंगी है, कमी है, सभी चीजों को चाहे वह अकाल के रूप में या चाहे मुफलसी के कारण है, जब तक अभाव की साझेदारी तंगी और कमी से अपने देश में कायम नहीं कर देंगे तब तक हम किस मुह से जनता को कहेंगे कि तुम तकलीफ उठा कर इस देश को बनाओ। जो लोग इस देश क

[डा० राम मनोहर लोहिया]

निर्माण करने वाले हैं, कानून बनाने वाले हैं, सरकार को चलाने वाले लोग हैं, यदि वे विलासिता में रहते हैं, ठाठ-बाट मे रहते हैं, उन के मुंह में यह शक्ति नहीं है कि वह जनता को कह सकें कि तुम मन लगा कर और पेट काट कर के देश का निर्माण करो और इस सम्बन्ध में. . . .

श्री जी० भा० कृपालनी (गुना) : कहते ही हैं।

डा० राममनोहर लोहिया : वह कहते हैं लेकिन खुद नहीं करेंगे। इसीलिये दादा मैं एक बात कहना चाहता हूं। और वह है सरकारी नौकरों के बारे में। प्रायः एक करोड़ सरकारी नौकर हैं .....

श्री जी० भा० कृपालानी : वह मालिक हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्योंकि हमारा देश-समाज सरकार अभिमुख है, और सरकार अफसर अभिमुखत हैं, यानी जनता सरकार की नौकर है और सरकार अफसरों की नौकर है। किसी हद तक मैं सही बात कह रहा हूं। अगर दादा आगे नहीं टोकेंगे तो बात पूरी कर सकूंगा। नहीं तो इन्हो मसलों में रह जाऊंगा।

एक करोड़ के करीब सरकारी नौकर हैं, उन में से बहुत से ऐसे हैं जो कोई भी पैदावार बढ़ाने का काम नहीं करते, कलमघिसू लोग हैं, उपजाऊ लोग नहीं हैं और यह बिल्कुल निश्चित बात है कि जैसे और देशों में पार्किन्सन नाम का नियम लागू है—हमारे देश में कुटुम्बे के कारणवश, जाति के कारणवश, प्रदेश और भाषा के कारणवश लोग खाली जगहें समाज में और सरकार में बनाया करते हैं, इसलिये नहीं कि कोई जरूरत है, बल्कि खाली जगहों का निर्माण करो, जिस में अपने कुटुम्बियों, जातिवालों, भाषा वालों को भर सको। मेरा अनुमान है कि 30-40 लाख आदमी ऐसे हैं, जिन की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वह सरकारी काज काम में लगे हुए हैं, इस से कितनी फ़िज़ुलखर्ची होती है। इस का अन्दाजा लगाना मुश्किल है। 30-40 लाख न सही, यदि हम 20 लाख को ही मान लें, तो इन से 300 करोड़ रुपये की बचत हो जाती है।

एक माननीय सदस्य : आप का सुझाव है कि इन को निकाल दिया जाय।

डा० राम मनोहर लोहिया : जो आज भारत की छाती पर बैठे हुए मूंग दल रहे हैं यह 300 करोड़ रुपया बच सकता है। लेकिन यह सरकार कुछ नहीं कर उकती, जब तक कि वे खुद अभाव और तंगी को सहने के लिये तैयार नहीं हैं और दुनिया को दिखा नहीं देते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह से तकलीफ उठा रहे हैं। मैं इन को बरखास्त करने की बात नहीं कह रहा हूं—मैं यह कह रहा हूं कि इन सरकारी नौकरों को कलम-घिसाऊ कामों से हटा कर उपजाऊ कामों में लगा दीजिये, जिस में कि वे देश की दौलत को बढ़ावा देने के काम में लग सकें। यह काम सरकार कर सकती है, जिस के लिये कि मैं ने यह बहस यहां पर उठाई है। आज क्या हो रहा है? एक तरह से यह सरकारी चलती रह गई तो हमारा देश यादवस्थली बन जायगा। आज हर एक वर्ग महंगाई भत्ता मांग रहा है, बनर्जी साहब महंगाई भत्ते की मांग को बढ़ावा दे रहे हैं, मैं उन से कहना चाहता हूं कि वह सही कदम क्यों नहीं उठाते, ऊपर के लोग विलासिता में क्यों रहते हैं? मैं अगर मजदूर नेता होता, तो मैं महंगाई भत्ते का बात नहीं करता, मैं यह मांग करता कि बड़े लोगों के खर्च घटाये जायें, ताकि चीजों के दाम घट सकें और हमारा समाज अच्छी तरह से चल सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : इन्दुराजी से हम ने यही तो कहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : बिरला, सरकारी नौकर जितने ये बड़े बड़े लोग हैं,

इन सब के खर्चे घटाये जायें, तभी जा कर हम अपने समाज को बना सकेंगे ।

आप को मैं ने रकमें बताई हैं, रकमों पर ज्यादा जोर मत देना, मैं तो बहुत डर डर कर हजार करोड़ कह रहा हूं, लेकिन मेरा अन्दाजा 1500 करोड़ रुपये का है । दो मंत्रियों ने यहां पर 25 करोड़ कहा है—एक तो श्री अशोक मेहता ने और दूसरे श्री मोरारजी देसाई ने । श्री अशोक मेहता के कभी ताजगी के दिन थे, पुष्प प्रफुल्लित हुआ था । मैं नहीं जानता श्री देसाई का फूल कब खिला था या नहीं खिला था, उन्हों ने कोई निशानी नहीं छोड़ी, लेकिन श्री मेहता ने निशानियां छोड़ी हैं, और मैं एक निशानी पढ़ कर सुनाता हूं—वह यह है कि—

"In India, 0.14 per cent takes five per cent of the national income."

जिस का मतलब हो जाता है—सात लाख, यानी डेढ़ लाख परिवार कमाने वाले, 10 अरब रुपया पा जाते हैं आज की राष्ट्रीय आमदनी के हिसाब से । मैं यह मानता हूं कि उन्हों ने जब यह किताब लिखी थी 1953 में तब से समानता और ज्यादा घटी है, असमानता बढ़ी है, 10 अरब रुपये से ज्यादा हो जायगी, लेकिन यदि 10 अरब ही मान लिया जाय और मेरा 1500 करोड़ रु० वाला नियम लागु कर दिया जाय, इन डेढ़ लाख कुटुम्बों पर, तो ढ़ाई अरब रुपया खर्च होगा और 750 करोड़ रुपये की बचत हो जायगी ।

यह है श्री अशोक मेहता की ताजगी के जमाने की, जब उन की कली खिली थी, उस जमाने की बात । अब यह पच्चीस करोड़ पर आ गए हैं । श्री मोरारजी देसाई की मुझे पता नहीं है कि कली खिली थी । जरूर खिली होगी । लेकिन नमूना मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं नहीं कह सकता हूं ।

अगर कुछ लोग समझें कि मैं यह ऐसे जमाने की बात कर रहा हूं कि जब अशोक मेहता साहब किसी तरह से लिख गए तो मैं जो व्यापारी लोग हैं जैसे यहां पर कुछ महानुभाव बैठे हुए हैं, कुछ लोग इन में से मेरे दोस्त हैं, युवा जन हैं और स्वतन्त्र पार्टी में होते हुए भी एक आध को मैं जानता हूं, उन से बात करने में मजा आता है । जवान लोग हैं । लोबो प्रभु जैसे नहीं जिन को संविधान की याद आ जाया करती है पीलु मोदी जी भी हैं, मनू जी हैं, जो मजे के आदमी हैं । हमारी उन से कोई लड़ाई नहीं होने वाली है । अभी कम से कम मैं राष्ट्रीय आदमी के कुल विताण में नहीं जाऊंगा क्योंकि किस्सा लम्बा हो जायगा । खाली इतना समझिये कि अगर मेरा नियम लागु कर दिया जाए तो इस व्यापारीयों के चेम्बर की किताब के अनुसार भी 57 करोड़ बचता है। मैं खाली कहे देता हूं कि कितने लोग हैं, इस के बारे में आप आय-कर के जो कमिश्नर हैं उन की किताब के आंकड़े से मेरा जवाब देंगे तो वह बिल्कुल गैर-जरूरी, बेमतलब, असंगत जवाब होगा । उस का कुछ भी मतलब नहीं हो पाता है । इसलिए कि सब लोग आयकर देते नहीं हैं । कम देते हैं । 57 करोड़ का तीन गुना कम से कम करना चाहिये । लेकिन अगर दो गुना भी आप करो तो 114 करोड़ रुपया तो ऐसा है जो उद्योगी रकम है, आमदनी उस में से बच जाएगी, खेती वगैरह का भी उतना शामिल कर लो तो तीन सौ करोड़ इन लोगों के हिसाब से बचता है । एक एक जगह से अगर मैं हिसाब लगा कर बताऊं तो यह साबित कर सकता हूं कि कितना ज्यादा रुपया बचता है ।

एक बार बहस हुई थी । ननदा जी बैठे हुए हैं । इन्हों ने एक बात को माना था । इन के उस वक्त के मुखिया के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा । इन्हों ने साढ़े सात आने माना था । मोटे तौर पर आठ आना सही । मैं ने तीन आना कहा था । मैं अब चार आना बढ़ाये देता हूं । अगर उस तरह से देखा जाए तो औसत आमदनी जितनी है और जो साठ सैंकड़ा जनता को कम मिलता है श्री नन्दा

[डा० राम मनोहर लोहिया]

के जब वह मंत्री थे कहने के अनुसार–अब पता नहीं कौन योजना मंत्री हैं, लेकिन ये गृह मंत्री भी रह चुके हैं—तो 6000 करोड़ रुपया बच जाता है और मेरे हिसाब से नौ हजार करोड़ रुपया. . . .

Mr. Deputy-Speaker: One minute. As you are counting the income, I must count the time. Two hours have been allotted. A number of hon. Members would like to speak. If the House desires more time, that is a different matter. But let us try to be brief. What I would suggest is, I will allow you 20 minutes; that means, by lunch hour, at I O'clock, you will have finished your 20 minutes' time. I have cautioned you.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : आज खाने की छुट्टी न रखिये ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अभी तो मैं आधा भाषण भी नहीं कर पाया हूं। दस बारह मिनट अगर आप और दें तो खत्म कर दूंगा ।

Mr. Deputy-Speaker: It is not possible; we have got private members' business.

श्री कमल नयन बजाज (वर्धा): दो घंटे की डिबेट है और बीस मिनट माननीय सदस्य बोल चुके हैं। दस बारह मिनट और लेंगे तो दूसरे क्या बोलेंगे—

Mr. Deputy-Speaker: I have calculated the time. If you want no reply from the other side, I will request the minister not to say anything. But after all, the debate must serve some purpose. I must find some time for the Minister's reply. You should furnish by lunch.

डा० राम मनोहर लोहिया : दो घंटे के बजाय चार घंटे कर दें। लोगों को बहुत अधिक चुभ रहा है।

श्री शिव नारायण (बस्ती): आप इनको दस बारह मिनट दे दें इसमें क्या एतराज की बात है। आज नान-आफिशल बिजिनेस है, उसमें से दे दें।

डा० राम मनोहर लोहिया : कितना वक्त मेरा ऐसे बरबाद हो जाता है। व्यवस्था के प्रश्नों आदि में चला जाता है। मेहरबानी करके मुझे ज़रा बोलने दीजिये।

यह हो सकता है कि जो मैंने छः हजार करोड़ रुपये की बचत बताई है वह सब की सब बड़े लोगों को न मिलती हो, मध्यम लोगों को मिल जाती हो। लेकिन उस हिसाब से हजार करोड़ रुपये का जो मैंने हिसाब रखा है वह गलत नहीं होता है।

एक बार यहां पर नोबल पुरस्कार विजेता श्री पाउलिंग आए थे। उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में हालत गिर रही है। उस पर बहुत ज्यादा हल्ला मचा था। सवाल जवाब हुए थे। जवाब ठीक तरह से लोग नहीं दे जाए थे। अगर सरकार के अपने नैशनल कंजम्पशन सर्वे राष्ट्रीय खपत सर्वेक्षण को देखा जाए तो उसके अनुसार जो नीचे के बीस सैंकड़ा लोग है, आबादी है उसके तरल पदार्थ यानी तेलों में और मीठी चीजों में कमी हुई है। यह सरकार ने खुद माना है।

हो सकता है कि मेरी बात पर कुछ लोग कहें कि तुम काम देश में कम करवा दोगे क्योंकि काम के अनुसार मजदूरी या मुनाफा मिलना चाहिये। इससे किसी को प्रेरणा नहीं रहेगी। यदि प्रेरणा नहीं रहेगी तो कैसे काम चलेगा। ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि जब राजाजी बारह सौ एकड़ के मकान में रहते थे तब जितना वह काम करते थे मेरा अपना अनुमान है कि उम्र बढ़ जाने पर भी अब एक चौथाई एकड़ के मकाम में रहते हुए उससे भी ज्यादा काम

वह करत हैं। हैं मैं चाहता हूं कि वह सौ बरस काम करत चले जायें। इस तरह से काम का मजदूरी और धन से ताल्लुक नहीं रहता है।

नौकरशाह और नगर सेठ के सम्बन्ध को आप जरूर जान लो। नौकरशाह अपने देश में ज्यादा हैं, नगर सेठ कम हैं। तीस लाख मान लो नौकरशाह बीस लाख मान लो नगर सेठ या बीस लाख दोनों मान ली तो बारह लाख नौकरशाह और आठ लाख नगर सेठ। ये जितने लोग हैं इन सबके बारे में कराची प्रस्ताव में जो गलती गकी गई है वह गल्ती अब हम लोगों को दोहरानी नहीं चाहिय। वह गलती यह है कि सरकारी नौकरों और मंत्रियों की तनख्वाह को तो बांध देना, कम कर देना, आदर्शमय बना देना और चारों तरफ उनके लालच का समुद्र बहा देना, सरकारी नौकरों और मंत्रियों को आदर्श के द्वीप में बैठा देना और नगर सेठों को लालच के समुद्र में बहते रहने देना। यह चीज असम्भव है। लालच के समुद्र में और सब जगह जब लगाम लगाओगे तभी जा कर सरकारी नौकर और मंत्री लोग अपन काम में ईमानदार बनेंगे और आदर्शवादी बनेंग।

अब एक सवाल उठता है। कई लोग कहत हैं कि तुम खपत और खर्च के ऊपर क्यों जोर देते हो। राष्ट्रीयकरण की बात क्यों नहीं करत हो। एसे लोगों से में खाली इतना कहूंगा कि मेरा प्रस्ताव बहुत आगे जाता है। यह क्या चुटकले लगाते हुए कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो इस प्रस्ताव के पास होने के बाद जो लोग समझते हैं कि उनको काम करने की प्रेरणा नहीं है उन सबका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। अगर प्रेरणा लोग समझते हैं तो हम ऐसी बात भी सोच सकते हैं। मैंने सुना है कि संतान वगैरह के मामले में आदमी जरा कुछ बहुत ज्यादा आतुर रहता है और उसकी भावनायें रहती हैं। कुछ रुपया बीस बरस तक हम उनके नाम में जमा करते रह सकत हैं। इस के कारण यह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूं वह केवल बीस बरस के लिए कह रहा हूं। अपना देश जब भरपूर हो जाए उसके बाद जो आपको करना हो कर लो। ये पैसे आप चाहो तो उनको दे दो, उनकी सन्तानों को दे दो। लेकिन बीस बरस तक इस तरह से जैसा मैंने बताया है काम चलाओ।

कई बार लोग कहते हैं कि तुम्हारी अपनी क्या हालत है। मैं पहले से बता देता हूं कि यह विशेषाधिकार का समाज है। मेरी तनख्वाह पांच सौ रुपय मासिक है लेकिन सुविधाओं के हिसाब दे से देखा जाए तो जिस ढंग का मुझे मकान मिला हुआ है और जो सुभीते हैं उन सबको जोड़ा जाए तो ढाई हजार रुपया माहवार तनख्वाह बैठती है। जहां मैंने अपनी बात कही वहां में मंत्रियों की भी कह देना चाहता हूं उनको करीब सात हजार महीना मिलती है और वह साल की जा कर एक लाख के करीब पड़ती होगी। और ठाट-बाट के क्या कहने है! मैंने राष्ट्रपति भवन के बारे में एक बार कहा था कि खाली लिफ्ट बदलने के लिये चालिस लाख रुपया खर्च करने की योजना बनी थी जिस में से पांच छः लाख रुपया खर्च भी हो गया

13 hrs.

कहने के लिए तो राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री में से प्रत्येक पर दस बीस तीस लाख रुपया खर्च होता है लेकिन मैंने साबित कर दिया है कि उन में से प्रत्येक पर कम से कम एक करोड़ रुपया साल का निजी खर्च होता होगा। इतने ठाट-बाट इतनी शानों-

[डा० राम मनोहर लोहिया]

शौकत इतना ऐश्वर्य इतनी शौकीनी क्या हम लोग यूरोप और अमरीका की नकल करके अपने देश में पैदावार बढ़ाना चाहते है? अगर पहले हम बीस वर्ष तक पैदावार बढ़ा ले और उस के बाद उस ऐश्वर्य की नकल करें तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा।

मैं खुद चाहता हूं कि मैं आराम से रहूं। एक रूसी से मेरी दोस्ती हो गई थी। शायद वह रूस की सी० आई० ए० वाला रहा हो। वह दिन में दोबार मेरे पास आने लग गया। यह ताशकंद से पहले की बात है। अब तो उन की शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम अपने घर में वातानुकूलित करने वाली ठंड करने वाली मशीन क्यों नहीं लगा लेते; तुम इस तरह काम कैसे कर सकते हो; मजदूरों का भला कैसे करोगे। मैंने कहा कि पहले मुझे अपने देश को तुम्हारे रूस जैसा एक आधुनिक पैदावार वाला देश बनाने दो फिर वातानकूलित करने वाली मशीन की बात करना।

मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि मैंने अपने प्रस्ताव में यह नहीं कहा है कि लोग अपनी चीजों को छोड़ दें। वह तो धर्म के लोग करते हैं। धर्म के लोग एक तो प्रेरणा पर काम करते हैं और दूसरे सन्तई पर काम करते हैं। राजनीति के लोगों का काम प्रेरणा पर चलता है और दूसरे विधि और कानून पर चलता है। हम लोग यहां पर कोई सन्तई करने नहीं आए हैं हम लोग विधि और कानून बनने आए हैं ताकि करोड़ों के लिए कोई काम किया जा सके न सिर्फ एक दो चार आदमी सन्त बन कर उदाहरण रख दें और लोग कहें कि कितने अच्छे और बढ़िया आदमी हैं।

इसी लिए मैं आप को एक बड़ा भंडार बताना चाहता हूं और वह है सिंचाई वाला भंडार। मैं ने एक मोटा सा हिसाब लगाया है कि पूरी खेती के लिए सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए 40 अरब से 1 खरब रुपये की जरूरत पड़ेगी एक खरब रुपये यानी दस हजार करोड़ रुपये। मैं समझता हूं कि इतना ज्यादा सिंचाई का काम करना असम्भव है जब तक हम स्वयं सेवकी को न शामिल कर लें और वह स्वयंसेवकी भी असम्भव है जब तक हम सारी जनता के सामने यह आदर्श न रख दें कि हम ने इस देश में अभाव की सांझेदारी करनी शुरू कर दी है।

कुछ लोग यह सवाल उठायेंगे कि क्या मैं निजी धंधे और सार्वजनिक धंधे जैसे बड़े विषय के बारे में कुछ नहीं करूंगा। मैं ने तो बुनियादी बात कह दी है। मैं आप से बड़ी गम्भीरता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर इस देश को चलाने वाले लोग चाहे वे निजी धंधे वाले हों और चाहे सार्वजनिक धंधे वाले इतने नादान हों कि वे कहें कि चलो कोई बात नहीं है हम अपने कारखानों का माल हिन्देशिया भेजेंगे, बर्मा भेजेंगे या और कहीं भेजेंगे और उन से चावल और गेहूं मंगायेंगे—यह बात केवल सार्वजनिक धंधे वाले ही नहीं कह सकते हैं निजी धंधे वाले भी कह सकते हैं—तो यह वही ग़लती होगी जो कि इस देश में पिछले बीस बरस से हो रही है यानी नाईलोन रेयन टेरीलीन वग़ैरह के न जाने कितने वाहियात किस्म के कारख़ाने तो बन गए और सिंचाई का काम नहीं हो पाया।

जो लोग कहते हैं कि उपभोक्ता पर छोड़ दो खुला धंधा छोड़ दो मैं उन्हें कहूंगा कि ऐसा करने का नतीजा आज हम देख ही रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि सार्वजनिक धंधे बनाए जायें मैं उन्हें कहूंगा कि राउरकेला और जमशेदपुर में आज कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह से लूट जमशेदपुर में है उसी तरह लूट राउरकेला में भी है क्योंकि वहां पर उसी तरह की अफ़सरशाही ही नौकरशाही और मज़दूरों का शोषण है और मैं तो यहां तक कहूंगा कि शायद कुछ

ज्यादा है, क्योंकि वहां पर अपनी जाति और अपने कुटुम्ब के लोगों को भरने का काम चलता आ रहा है।

असल में यह मामला सम्पत्ति का है। सम्पत्ति का मोह और सम्पत्ति की संस्था, मैं समझता हूं कि संसार में अभी तक किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी देश में एक-साथ इन दोनों का हल नहीं निकाला है। मार्क्स साहब ने सम्पत्ति की संस्था का हल निकाला था। हमारे उपनिषदों ने सम्पत्ति के मोह का हल निकाला था। इसी तरह से हम कोई ऐसा रास्ता निकालें कि सम्पत्ति के मोह और सम्पत्ति की संस्था, इन दोनों का हल निकाल सकें, भोग की इच्छा और भोग की व्यवस्था, दोनों का हल निकाल सकें। मैंने यही बात यहां पर रखी है कि किसी तरह से भोग की व्यवस्था पर रुकावट लगाई जाये, भोग की इच्छा पर रुकावट लगाई जाये।

मैंने अभी मोटर का उदाहरण दिया है। मैं अब स्कूल का उदाहरण देता हूं। हमारे देश में पांच दस लाख बच्चे ऐसे हैं, जो बढ़िया स्कूलों में जाते हैं, जो बीस तीस, पचास, अस्सी, सौ रुपये महीना की फीस देते हैं--खाली फीस, बस वाली फीस स्कूल वाली फीस, कपड़े और खाना नहीं। अगर उस खर्च को रोक दिया जाये और ऐसे, स्कूल हो जायें, जिनमें राष्ट्रपति का बच्चा और भंगी का बच्चा दोनों एकसाथ पढ़ने जायें, तो इससे भी कम से कम साठ करोड़ रुपये से एक अरब रुपये की बचत हो जायेगी।

अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि जो बातें मैंने कही हैं, सभी माननीय सदस्य इस विषय पर बोलते हुए उन पर ध्यान दें। मैं सम्पत्ति के मोह, भोग की इच्छा, सम्पत्ति की संस्था और भोग की व्यवस्था दोनों के बारे में कह रहा हूं। मैं अपने देश के लिए एक ऐसा रास्ता निकाल रहा हूं, जिस पर अभी तक लोगों ने नहीं सोचा है। माननीय सदस्य उस पर गम्भीरता से सोचें और देश का निर्माण करें।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That this House resolves that the Government should appoint a committee to work out the proposals for restricting individual monthly expenditure to Rs. 1,500 in order that Rs. 1,000 crores may annually be made available for investment in developmental work."

13.08 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after lunch at 4 minutes past Fourteen of the Clock.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

MOTION *RE.* APPOINTMENT OF COMMITTEE FOR RESTRICTION OF INDIVIDUAL MONTHLY EXPENDITURE—*Contd.*

Mr. Deputy-Speaker: Before we take up further discussion of Dr. Lohia's motion may I say that we have got to take up the non-official business at 3 o'clock but we will push it, with your permission, to 3.30.

Shri S. Kandappan (Mettar): 4 o'clock.

Mr. Deputy-Speaker: Even if I push it to 4 o'clock I cannot accommodate all. I have got about 50 names here. He has raised a fundamental issue. There is a sort of a debate there and outside. He does not expect—it is clear from his motion itself—that here and now we can take a decision. He wants a Committee to be appointed.

श्री मधु लिमये : शायद मोरार जी भाई मान लें।

Mr. Deputy-Speaker: May I know how much time the Deputy Prime Minister would require?

The Deputy-Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): As much time as you would like to give me. I cannot say anything. If you do not give me any time, I am content.

Mr. Deputy-Speaker: Approximately 20 minutes?

Shri Morarji Desai: Whatever time you give, I will occupy it more usefully than Dr. Lohia.

Mr. Deputy-Speaker: You can have 10 minutes for your reply.

डा० राम मनोहर लोहिया : आप जो हुक्म देंगे ।

Mr. Deputy-Speaker: You had your satisfaction of starting the debate. Now, I will give 5 to 7 minutes to other hon. Members. Dr. Sushila Nayar.

An hon. Member: There is an amendment also.

Mr. Deputy-Speaker: The mover of the amendment was not present.

डा० सुशीला नायर (झांसी) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय डाक्टर लोहिया साहब ने यह जो प्रस्ताव रखा है कि खर्चे पर अमुक बन्धन लगाया जाय और अमुक हद् से ज्यादा लोग खर्चा न करें यह प्रस्ताव तो अच्छा प्रस्ताव है, इस में दो रायें नहीं हो सकतीं । आज जब इतनी मुसीबत में से, आर्थिक संकट में से देश गुजर रहा है, हम अपनी जरूरियात पर कम खर्च करके देश के नवनिर्माण के लिये धन लगायें, इसमें कोई दो रायें नहीं हो सकतीं । यह अच्छी बात है । श्री लोबा प्रभु जी ने कहा कि इसमें कांस्टीट्युशनल रूकावट आयेगी तो अगर इन्होंने आमदनी के ऊपर रोक लगाने को कहा होता तब तो कांस्टीट्यूशनल रुकावट की बात आ सकती थी, फंडामेंटल राइट्स की बात हो सकती थी । लेकिन अपना पैसा आप खर्च न करें अपने ऊपर, और देश के लिये रखें, इसमें कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ।

मगर उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो कुछ तरीके बताये मुझे शक है कि वह तरीके कारगर नहीं हो सकते हैं । उन्होंने कहा कि मोटर किसी के पास प्राइवेट न रहे । 4 लाख मोटर गाड़ियो हटा दें और 5 सौ रुपये का जो एक एक गाड़ी के पीछे खर्चा होता है वह बच जायगा । अब या तो मोटर गाड़ियां देश में रहे नहीं, हम बैलगाड़ियों में चलें। लोहिया जी यह चाहते हों तो कुछ बात हो सकती है, लेकिन अगर मोटर गाड़ियां चलनी हैं और मैं समझती हूं कि डा० लोहिया भी बैलगाड़ी में नहीं चलेंगे, मोटर गाड़ियों पर ही जायेंगे, तो मैं यह कहना चाहती हूं कि मोटर संस्था की ओर से चले या व्यक्ति की ओर से चले खर्चा, तो उनके ऊपर होगा ही । खर्चे की बचत नहीं होगी । और मैं यह भी उन से निवेदन करना चाहती हूं कि मोटर गाड़ी आखिर डाक्टर हैं तो उसको चाहिए, आप माननीय सदस्य हैं, आप को पांच दस जगह पर जाना है तो आप को भी शायद जरूरत पड़ेगी । इसी प्रकार से कई और लोग हो सकते हैं । यह पत्रकार लोग हैं, इन को एक जगह से दूसरी जगह दौड़ भाग करनी होती है । तो गाड़ियां रहेंगी । अब मोटर गाड़ियां व्यक्ति के द्वारा चलायी जायं या संस्था के द्वारा इतना ही फर्क रह जाता है । जो कोई भी चलायेगा उसके ऊपर पेट्रोल भी लगेगा, ड्राइवर भी होगा, खर्चा भी होगा, मेंटिनेंस भी होगा, रिपेयर भी होगा । तो वहां कोई बचत होने वाली नहीं है । और मेरा नम्र निवेदन है माननीय लोहिया जी से कि मोटर गाड़ियां हम तो चाहते हैं कि ज्यादा बनें, सस्ती बनें और सर्वसामान्य लोग भी मोटर गाड़ियों का उपयोग कर सकें जैसे मोटर साइकिल का कर रहे हैं । लेकिन इस वक्त तो मोटर गाड़ियों के दाम बहुत ज्यादा हैं । वह दाम इसलिए हैं कि कुछ मोनोपली है, कुछ कम संख्या में बनती हैं, कई एक उसके कारण हैं तो मैं यह कहूंगी कि जिस चीज को आप आवश्यक समझते हैं वह चीज आप को

देनी पड़ेगी, चाहे भाप फिर उसकी किसी तरीके से दो, व्यक्ति को दो या सामूहिक रूप से उसका उपयोग करो। मोटर गाड़ियां बननी अगर बन्द हो जायेंगी तो इतने लाख लोग जो उसमें काम करने वाले हैं वह भी बेकार हो जायेंगे, यह भी सोचने की बात है। तो यह चीज नहीं चल सकती।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : खेती पर सब लोग जाकर काम करें।

डा० सुशीला नायर : हम जानते हैं कि इस देश में खेती पर काम करने वाले इतने ज्यादा लोग हैं उनके लिये पर्याप्त काम नहीं है, पूरा काम उन्हीं के लिये नहीं है। आज तो यह कहा जा रहा है, सब की तरफ से, और लोहिया जी की तरफ से भी कि जमीन पर से कुछ लोगों को हटा लें ताकि वह ज्यादा उत्पादन कर सकें। जमीन के अलावा दूसरी जगह दूसरे साधनों से . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : ट्रैक्टर और पम्पिंग सेट वगैरह बस।

डा० सुशीला नायर : पम्पिंग सेट वगैरह यह जो कह रहे हैं, वह भी बनें। मगर बनाने का काम हरेक नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि जो चीजें आपको वाहन के लिये, ट्रांस्पोर्ट के लिये चाहिये, उसके बगैर आपका गुजारा नहीं चलेगा। दूसरी चीजें भी चलें, जो साधन आपको चाहिये, उनके लिये मैं वित्त मंत्री से कहूंगी कि जितना धन उस तरफ़ डाल सकते हैं, डालें, लेकिन यह कहना कि खेती में लोग ज्यादा काम करें, यह नहीं हो सकता, साथ में उद्योगों में भी लगें, तब यह हो सकता है। आज खेती के साथ उद्योग रखने की आवश्यकता है ताकि खेती में काम करने वालों को पर्याप्त आमदनी हो सके। आज केवल खेती से पर्याप्त आमदनी नहीं होती है, बहुत ज्यादा लोग जमीन में लगे हुए हैं।

आप ने कहा कि एक करोड़ इस समय सरकारी नौकर हैं, इन में से 20 लाख को कम से कम निकाल दिया जाय, इनको निकाल कर कहां फेंका जायगा, यह कोई मजाक तो नहीं है। जहां कहीं जरा भी रिट्रेन्चमेन्ट होता है, हल्ला मच जाता है, हमारे भाई बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि आखिर वे लोग कहां जांय, कैसे रोटी खांय। यह ठीक है कि भविष्य में सरकारी नौकरों की भरती कम की जाय, नये एक्सपेन्शन में उनको लगाया जाय—यह चीज मानने की है, आवश्यक है, और उस दिशा में कुछ काम हो भी रहा है। लेकिन 20 लाख नौकरों को निकालना—यह नहीं हो सकता है। चौधरी चरण सिंह ने 3500 औरतों को निकाल दिया है, उन्होने वहां हल्ला बोला हुआ है, वे कहां जांय, उनमें कोई विधवा है, कोई परित्यक्ता है और कोई अपने मां-बाप का पेट पाल रही है, उनके साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, यदि 20 लाख को निकाल दिया तो क्या होगा—इस देश में।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे यही कहना है कि जो आप कहते हैं कि खर्च कम हो, आस्टेन्टेशस स्पेन्डिग न हो—यह बात तो समझ में आती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पैसे से घर बना लेता है उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिये, घर तो हर एक को सरकार नहीं दे सकती—तो यह देख लीजिये कि कुछ प्रोडक्टिव चीजों में धन लगे, उसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये, हां, आस्टेन्टेशस स्पेंडिग नहीं होना चाहिये।

मैं इस बात का भी समर्थन करती हूं कि रेयन नाईलोन के कारखाने नहीं लगाने चाहियें बल्कि उस धन का उपयोग ऐसे कामों में होना चाहिये, जिससे गरीब जनता को काम मिल सके और आवश्यकतायें पूरी हो सकें। आज जो करोड़ों रुपये की खादी गरीब औरतों के मेहनत और पसीने की बनाई हुई पड़ी है, उसकी खपत हो सकती है,

[डा० सुशीला नायर]

उन गरीब बहनों के बाल बच्चों को पालने का साधन मिल सकता है, यदि टैरिलीन और लाइलोन के कारखाने न हों तो। जो पैसा लगाया जाता है उनमें अन्य प्रकार के उत्पादन के कार्य में क्यों नहीं लगाया जा सकता है। इसलिये मैं आप से यह कहना चाहती हूं कि यह चीज बड़ी गम्भीरता से सोचने की है कि किस प्रकार से यह हो सकता है। जो तरीके लोहिया जी ने बताये हैं, वे नहीं चल सकते हैं।

आप ने स्कूलों की बात कही है। मैं चाहती हूं कि सब स्कूल अच्छे हों, लेकिन आज ऐसा नहीं है। यदि कोई मां-बाप अपना पेट काट कर अपने बच्चों को अच्छी तालीम देने के लिये मिल कर कोई सामुहिक साधन कर लेते हैं तो इसमें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह ठीक है कि हमारे स्कूल अच्छे बनें, उसका प्रयास होना चाहिये। लेकिन जब तक यह नहीं होता है, तब तक इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये कि जो मां-बाप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं, वे दें।

मुझे इतना ही कहना है कि सम्पत्ति का मोह न हो, सम्पत्ति की संसथा की तरफ़ तवज्जह दी जाय—यह मैं मानती हूं, लेकिन मैं डा० लोहिया जी से नम्र निवेदन करते हुए यह कहना चाहती हूं कि जब वह सेवाग्राम में बापू जी के पास बैठते थे, उस समय की बातों की तरफ़ तवज्जह दें, जो रास्ता बापू जी ने बताया था, उसको अपनायें। हमें अपने विचारों में परिवर्तन करना होगा, खाली कानुन बना कर, लोगों पर पाबन्दी लगा कर यह व्यवस्था सफल साबित नहीं हो सकेगी, कानुन की मदद लें, लेकिन ज्यादा तालीम की तरफ़ ध्यान दें। तभी खर्च कम करने की बात सफल होगी।

अब मैं प्रोहिबिशन की बात कहती हूं। आप उसका विरोध करते हैं। 1200 करोड़ रु० हर साल एक्साइज से इस देश में आता है। एक रुपया रेवेन्यु के पीछे 4 रु० पीने वाले खर्च करते हैं। अगर लोहिया जी हमारे साथ पूरा सहयोग दे कर शराब बन्दी को सफल बनायें तो इस तरह से पांच गूना—1200 करोड़ रुपया बच सकता है। अर्थात् 6000 करोड़ रुपये शराब में न जाकर उत्पादन में जा सकते हैं।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने शराब पीने को कभी नहीं कहा।

डा० सुशीला नायर : तो फिर बन्द करवाने में मदद करें।

Mr. Deputy-Speaker: Dr. Sushila Nayar should now conclude. Otherwise, it would not be possible for me to regulate the debate.

Now, Shri N. K. Somani. He will have to confine his remarks to not more than five to seven minutes. I shall be very strict in regard to the time.

Shri N. K. Somani (Nagpur): It is very difficult for me to participate inteligently in a discussion of a propasal which is basically so ill-conceived and frivolous and contrary to human nature, as the one that Dr. Ram Manohar Lohia has brought forward in this House. I suspect that Dr. Ram Manohar Lohia is now turning sadistic. It is indeed a pity that some times in his obsessions, he puts forward such propositions as this; sometimes, his obsessions are magnificient and sometimes they are not. But I do not know how I can argue with a person who dreams of imaginary mink coats and diamond necklaces; I do not know how to meet such a person either on ground or in air.

He has propounded a set of theories and come to entirely different conclusions. According to him, if you limit or cut down personal expenditure,

which, of course, is contrary to basic human nature, but which according to him is possible and should be done, this country will get about Rs. 1000 crores more per year which can be invested in productive enterprises. I say that this is completely contrary to human nature and this is completely wrong, because the moment you start doing such an ill-informed or ill-conceived thing, there will be absolutely no incentive left in this country to either work more or to produce more and thereby invest and save. The meagre savings which we have today in this country will rapidly dry out.

When he quotes Rajaji or when he quotes an ascetic like himself, there are absolutely different motivations that move people. When he talks of human nature, I would like to quote to him what Arjuna asked Lord Krishna in the Second chapter of the Gita, because he is talking in terms of *Sthithaprajna*, he is talking in terms of people who have no value for money, and he is talking of people who are ascetic, he is talking not of the ordinary Indian people but of people like Rajaji and people like himself. Arjuna asked Lord Krishna:

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।
स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् ।।

And Lord Krishna told him:

ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते ।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसके आगे भी जोड़ो—

कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः

Shri N. K. Somani: Dr. Ram Manohar Lohia: believes that every man in this country or elsewhere is a *sthithaprajna* and that every man has motivations that move Rajaji or him.

Now, let us go into the context or the circumstances that are facing the country today. I believe that the objectives of our national ecnomic policy are as follows. I am referring to this because he has mentioned the urgency of a sizable and massive capital formation; it may be that he wants to put that money into irrigation and agriculture. We have no fight against that. But how do you raise capital? You do not raise it by speaking such things and by propounding such questionable theories.

Capital can only come into the country either by taxation which is already so high,—thanks to the policies of our Government, it is 82.2 per cent to 89.4 per cent,— or by public borrowing, which is also extremely high, or by deficit financing which this time very wisely we have tried to give up or by foreign aid. I maintain that all these four basic avenues of capital formation have been so overtaxed that there is absolutely no further scope. Now, what is the purpose of throttling individual enterprise and individual savings? Even a gambler sometimes takes lessons in his life, but Dr. Ram Manohar Lohia does not seem to take any lessons from the 20 years of experimentation that we have done in this country and the results that we have come to, because he does not believe in resourcefulness, he does not believe in enterprise, he does not believe in the initiative of an individual, and I think he is against the Indian individual, and, therefore, he has tried to go one more step forward than what has been done in this country and he wants to throttle and kill complete initiative. If he wants to deny to an individual the right to spend money for what he wants, of course, legitimately, then where is the incentive for working more and producing more? He has even gone one more step and drawn a wrong conclusion in respect of the report of Dr. Mahalanobis submitted in February, 1964. I do not know what hallucinations he is suffering from. In his report on the distribution of income, Dr. Mahalanobis has said:

"The degree of inequality in income distribution is not higher in India than in some other develop-

[Shri N. K. Somani]

ed or under-developed countries, including the Soviet Union.".

I do not know whether the Gita moves him. But I would like to remind him of Stalin when he said in; 1931-32 that equality is a concept worthy of a primitive society and has nothing to do with socialism; he also said that it is a bourgeois deviation. I do not know whether the Doctor wants to usher in in India a society of that nature.

Then imagine for one moment if, God forbid, this Motion is passed, what is going to be the power of intimidation and blackmail in the hands of a few income tax officers? The ITOs will have full authority to come to your house and ask you where you got your litre of milk from, what fees you have paid for the education of your children, how much you have spent on your travelling, entertainment, cinema, education, foodgrains etc. I suppose Dr. Lohia would like to give all those powers to the ITOs. But I propose and I put forward the plea that this is going to increase corruption in our country and will also generate more black money instead of curbing it. If Dr. Lohia is endeavouring to reduce wasteful expenditure, non-developmental expenditure, my Party and I are both with him. But I would like to know from him as the big brother what he and his party which is associated with many State Governments today in this country have done. Will he tell us whether he has curtailed expenditure in the various State Governments with which he is associated? Will he tell us whether he has done anything by way of maximising production and productivity in the various States in the government of which he is supposed to have a say? Will he tell us whether he has increased or tried to increase productivity in various fields in the States in which he is supposed to have a stake? Will he tell us whether he has brought about an improved climate by eliminating the mutual distrust that exists between the Governments and the businessmen in those States in the government of which he has a say?

We are all with him if he has done any such thing.

Shri Nath Pai (Rajapur): Does he have a say there?

Shri N. K. Somani: I would like to find out. We are all with him if he is for curbing the price rise, the rise of 80 per cent in prices that has come about in the last ten years. But as far as this stupid and impractical proposal is concerned, it will kill initiative and enterprise and we are definitely not with him.

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० राम ममोहर लोहिया ने जो प्रस्ताव रखा है उस के पीछे जो भावना है, जो मंशा है उस का मैं आदर करता हूं। उन की मंशा यह है कि इस देश में जो वैभव, शान शौकत, अनावश्यक और दिखावे वाले कार्यों पर खर्च होता है वह बन्द किया जाय ताकि कीमत भी कम आ सके और देश के विकास के लिए बहुत बड़ी तादाद में साधन उपलब्ध हो सकें। जहां तक इन उद्देश्यों का संबंध है और उस के पीछे जो भावना है उस का मैं आदर करता हूं और समर्थन करता हूं लेकिन मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि जो भाव इन्होंने दिये हैं वह कोई रामबाण औषधि हैं या अमोघ अस्त्र हैं जिन से कि देश की सारी समस्याएं हल हो जायेंगी। मैं चाहूंगा कि डा० साहब इस समस्या की ओर जरा एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें। ऐसा लगता है कि डाक्टर लोहिया अब भी फेनियनिजम के प्रभाव से मुक्त नहीं हुए हैं। उनका सुझाव अवैज्ञानिक, अव्यवहारिक और काल्पनिक है। मैं उन का एक विरोधाभास आप के सामने रखना चाहता हूं। खर्चे पर आप एक सीमा बांध देंगे। वह कहते हैं कि उस से पैसा बच जायेगा लेकिन पैसा बचने से ही

वह देश के निर्माण में लग जायेगा उस का क्या आश्वासन हमें है। इस का अर्थ यह है कि वह चाहेंगे कि सरकार इस को मौप अप करे, उस को अनिवार्य ऋण के रूप में ले ले या और किसी प्रकार लेकर निर्माण कार्यों में लगाये। लेकिन उनके पूरे भाषण में इस बात का कहीं आभास नहीं मिला।

एक प्रश्न मेरे साथी सोमानी जी ने उठाया। बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है। वह कहते हैं कि फिर इंसटिव क्या होगा? यह एक दलील आम तौर पर इन लोगों की रहती है कि अगर आप ने खर्चे पर या आमदनी के ऊपर सीमा लगा दी तो हम क्यों कमायेंगे? हमें क्या इंसटिव रहेगा? इस संबंध में मुझे गोर्की का एक बड़ा सुन्दर लेख याद आता है। वह एक धन्नासेठ से मिलने गये। उस से गोर्की ने पूछा कि क्या तुम 10 कोट पहनते हो तो उस ने जवाब दिया कि नहीं एक कोट ही मैं पहनता हूं। उस से पूछा कि क्या तुम 100 बार खाते हो तो उस ने जवाब दिया कि नहीं मैं एक बार खाता हूं। उस से पूछा कि क्या वह 50 बिस्तर पर सोता है तो जवाब मिला कि नहीं भाई मैं एक ही बिस्तर पर सोता हूं। करते क्या हो? धन्नासेठ ने जवाब दिया कि पैसा बनाता हूं। इस पर गोर्की ने पूछा कि क्या टक्साल चलाते हो? उस ने जवाब दिया कि मैं टक्साल नहीं, कारखाने व मिलें चलाता हूं। गोर्की ने पूछा कि कितना पैसा बनाते हो तो उस ने कहा कि लाख रुपया। उस का क्या करते हो? और पैसा बनाता हूं। उस का क्या करते हो? और अधिक पैसा बनाता हूं। गोर्की ने जब फिर उस से सवाल किया कि उस का क्या करते हो तब उस धन्नासेठ के कहा कि तुम पागल तो नहीं हो। इस पर गोर्की ने उस धन्नासेठ को कहा कि मुझे तो आप पागल नजर आते हैं। इसलिए यह कोई खर्चा करने के लिए ही पैसा कमाते हो ऐसी बात नहीं है। यह एक विशेष प्रकार के प्राणी हैं जो उस एक चक्कर में फंसे हुए हैं। और कुछ वह कर नहीं सकते। इसलिए वह खर्चे के लिए ही पैसा कमाते हों ऐसी बात मैं सिद्धांत रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं। इसलिए केवल खर्चे पर सीमा बांध देने से समस्या हल नहीं होती है। खर्च करने के बाद भी खर्च के सारे दिखावे के पीछे आधार क्या है? इस के पीछे आधार यह है कि आज देश में एक समानान्तर मुद्रा चल रही है और समानान्तर मुद्रा कितनी है उस का कोई अनुमान नहीं है। टैक्स की कितनी चोरी होती है इस बारे में कालडोर लेकर रिजर्व बैंक ने उस के अलग अलग अनुमान लगाये हैं। देश में बहुत बड़े पैमाने पर समानान्तर मुद्रा चल रही है यह एक मानी हुई बात है। बहुत सारा काला धन सफेद धन हो चुका है और वही इस दिखावे का खर्चे का स्रोत है। यह जितना आज खर्चा दिखाई दे रहा है दिखावे का उस का एक कारण यह है कि वह काला पसा है जो खर्च हो रहा है जो कहीं सफेद बन रहा है और कहीं सफेद नहीं बन रहा है।

एक वक्त था जबकि हम डिमोनेटाइजेशन करके काले पैसे को फ्रीज कर सकते थे। आज भी यह किया जा सकता है बाकी इस को बहुत पहले कर देना चाहिए था। इस के साथ टैक्सों की चोरी को रोकने के लिए हमारे मंत्री महोदय श्री मोरारजी भाई बहुत सख्ती से कदम उठा रहे हैं। उस के लिए मैं उन का अभिनन्दन करना चाहता हूं। शहरी आमदनी पर सीमा बांधी जाय। डिमोनेटाइजेशन किया जाय और टैक्सों की चोरी को रोका जाय। यह एक इतना आसान प्रश्न नहीं है कि एक हल्की सी औषधि डा० राम मनोहर लोहिया बतला दें और उस से यह समस्या हल हो जाये। इस प्रकार यह जो कौंस्पीकुअस कंज्प्शन है उसे रोकना चाहिए उस को कर्ब करन चाहिए। इस का हमारी कांग्रेस पार्टी ने एलान किया है अपने चुनाव घोषणा पत्र में

[श्री अमृत नहाटा]

और अपने प्रस्तावों में और इस को रोकने के लिए, कीमतें नीची लाने के लिए और दूसरे जो कार्य हैं व ढ़ करने के लिए हम वचनबद्ध हैं और उन कार्यों पर अमल करने से ही यह उद्देश्य हल होंगे यह मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं डा० राम मनोहर लोहिया के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रस्ताव में यह कहा गया है कि व्यक्तिगत मासिक व्यय एक सीमा तक लाने के लिए और उस के संबंध में प्रस्तावों पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई जाये। मैं समझता हूं कि यह एक रचनात्मक सुझाव है और जिस दिशा में हमारे चिन्तन को और हमारे आचारों को जाना चाहिए उस दिशा में यह प्रस्ताव ले जाता है। डा० राम मनोहर लोहिया ने यह नहीं कहा कि व्यक्तिगत व्यय पर अभी रोक लगा दी जाय। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के प्रस्तावों को तैयार करने के लिए कमेटी बनाई जाये।

रोक कितनी सीमा पर लगेगी और रोक लगने के बाद कितना रुपया राष्ट्र के निर्माण के लिए प्राप्त होगा इस के निर्धारण का काम कमेटी पर छोड़ा जा सकता है। प्रस्ताव कितनी मात्रा में व्यवहारिक है, क्या कानून से यह सम्भव है या नहीं है, कौन सी कठिनाइयां पैदा होंगी, क्या उन का निराकरण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? मैं समझता हूं कि यह सारी बातें समिति को सौंपी जा सकती हैं और उस के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जा सकती है।

प्रश्न यह है कि यह सदन इस बात को चाहता है या नहीं कि हमारे देश में ऐश्वर्य का, वैभव का, अनापशनाप खर्च का, ठाठबाट का जो एक तरीका चल रहा है वह तरीका बन्द होना चाहिए। गरीबी और अमीरी में बड़ी खाई है। कुछ क्षेत्रों में यह खाई बढ़ती जा रही है। सभी स्वीकार करेंगे कि यह अन्तर अगर कम नहीं होगा तो इस के गम्भीर राजनीतिक व सामाजिक परिणाम होंगे। भारत के आम आदमी अब अधिक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे सामने आकांक्षाओं और अपेक्षाओं का बड़ा आलोड़न हो रहा है। स्वाधीनता के 20 वर्षों के बाद जिन लोगों को राष्ट्रीय समद्धि में हिस्सा नहीं मिला वह बेचैन हो रहे हैं। उन की बेचैनी लोकतन्त्र को भी खतरे में डाल सकती है। इस लिये यह प्रश्न एक सामाजिक स्वरूप का है जिस पर गम्भीरता से विचार करना होगा।

एक पहलू और है। गरीबी अमीरी का अन्तर है। यह खराब है। यह कम होना चाहिये, लेकिन इस से भी भयंकर अन्तर का प्रदर्शन है। अभी मेरे मित्र श्री सोमानी गीता की बात कर रहे थे। महाभारत में कुन्ती ने कहा कि मेरे दिन निर्धनता में बीत रहे हैं, यह मुझे इतना नहीं खलता जितना मुझे यह खलता है कि कौरव के दिन समृद्धि में बीत रहे हैं। जब कुंती जैसी महिला के हृदय में विषमता कसक सकती है तो भारत के आम आदमी पर वैभव के प्रदर्शन का क्या परिणाम होता है इस की गम्भीरता को हमें समझना चाहिये। और इस को सभी स्वीकार करेंगे कि हमारे देश में वैभव का प्रदर्शन बड़े भौंडे ढंग से किया जाता है।

क्या यह सम्भव नहीं है कि हम खर्च कम करें? क्या यह सम्भव नहीं है कि कानून भी इस दिशा में लोगों को प्रवृत्त करे। कितनी सफलता मिलती है इस के बारे में अभी से भविष्यवाणी करना ठीक नहीं होगा। उपभोग में संयम का जो हमारा आदर्श है उसे राज्य कानून द्वारा किस प्रकार चरितार्थ करवा सकता है, इस पर विचार होना चाहिये।

इस समय एक गम्भीर आर्थिक संकट है। इस संकट के निराकरण के लिये हमें तीन सूत्री विचार अपनाना पड़ेगा। उत्पादन में वृद्धि—चाहे खेती का उत्पादन हो या कल-कारखाने का—,उपभोग में संयम और वितरण में औचित्य। अब कहा जाता है कि हमने उपभोग में संयम कर दिया तो इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं हूं। कुछ व्यक्ति हो सकते हैं जो केवल मुनाफे के लिये काम करें, लेकिन इस से बड़ी प्रेरणा और कौन हो सकती है कि इस देश में फैले हुए अभाव, अज्ञान और बीमारी को दूर करने के लिये हम ऐसे राज और समाज की रचना करें जिसमें कोई भूखा न हो, नंगा न हो, कोई बीमार बिना दवा के न मरे, किसी का बच्चा अज्ञान में न रहे? इस से और महती प्रेरणा कौन सी चाहिये? यह प्रेरणा जिन्हें प्रेरित नहीं कर सकती, उनके लिये कानून का विचार करना होगा। भारत के सेठ और पूंजी-पति अगर आज इस कसौटी में खरे नहीं उतरेंगे तो मैं उन्हें चेतावनी देना चाहता हूं कि उन को दीवार पर लिखे हुए को पढ़ना चाहिये और देश का मानस जिस गति से बदल रहा है उस गति से उनको बदलना होगा, कष्ट में जीवन बिताना होगा। अगर वह खुद संयम या अनुशासन में नहीं रह सकते तो राज्य को आगे बढ़ कर उन्हें एक सामाजिक अनुशासन में रखना होगा।

Shri Sonavane (Pandharpur): Shri Vajpayee was against the abolition of privy purses.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order. Kindly conclude now.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा निवेदन है कि डा० लोहिया के प्रस्ताव में आमदनी पर रोक लगाने की बात नहीं कही गई है। इन्सेंटिव क्यों कम होना चाहिये? व्यक्ति परिश्रम करें। परिश्रम कर के आमदनी बढ़ाये। मगर उस आमदनी को इस तरह से खर्च करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता जिस से देश की दौलत न बढ़े और देश की जनता के मन में असन्तोष पैदा हो। प्रस्ताव पर विचार करते हुए यह बात ध्यान में रखनी होगी कि नियन्त्रण आमदनी पर नहीं है, नियन्त्रण पुरुषार्थ पर नहीं है, नियन्त्रण व्यय पर है, फिजूलखर्ची पर है, नियन्त्रण सस्ते ढंग की शान-शौकत पर है। इस पर रोक लगाने का समय आ गया है और मैं समझता हूं कि सारा मामला समिति को सौंपने में वित्त मंत्री को कभी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री कमलनयन बजाज (वर्धा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस भावना से यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया है या इस प्रस्ताव के पीछे जो भावना है, उस भावना के साथ मेरी पूरी हमदर्दी है।

डा० राम मनोहर लोहिया : इस प्रस्ताव पर बोलने के लिये क्या सब मारवाड़ियों को ही बुलाया जायेगा?

श्री मधु लिमये : डाक्टर साहब का विरोध करने के लिये सिर्फ मारवाड़ियों को ही बुलवा रहे हैं।

Mr. Deputy-Speaker: Has he brought forward the motion because he is a marwadi? I do not know why this point is being raised.

डा० राम मनोहर लोहिया : कभी कभी तो आप मजाक समझ लिया करें।

श्री कमल नयन बजाज : इसके पीछे जो भावना है मैं उसका साथ देता हूं कि जहां तक ऐश्वर्य वैभव और प्रमाद के प्रदर्शन का सवाल है, उससे समाज का नुक्सान होता है, व्यक्ति का नुक्सान होता है। मैं इस चीज को मानने वाला हूं। लेकिन इस समय हमारे सामने जो बड़ा प्रश्न है वह यह कि इस वक्त देश का धन और दौलत किस तरह से बढ़े। किस तरह से हम उसे उत्पादित करें, इसकी तरफ हमारा ध्यान अधिक होना चाहिये। साथ ही साथ उसका व्यय

[श्री कमल नयन बजाज]

फिजूलखर्ची की तरफ या जिसमें पैदाइश न हो उसकी तरफ न चला जाये, इसकी हम पूरी खबरदारी रक्खें तो मैं मानता हूं कि इससे विशेष लाभ होगा। संयम और त्याग के लिये भी एक वातावरण बनाने की दरकार है। लेकिन वह सिर्फ कानून से बनाया जा सकता है ऐसी मेरी मान्यता नहीं है। यदि लोक-सभा के सारे लोग एक नियम बना लें कि जहां पर इस तरह के ऐश्वर्य प्रमाद या वैभव का प्रदर्शन हो, चाहे वह किसी का विवाह हो या कोई पार्टी हो या कोई और प्रसंग हो, वहां पर वे लोग नहीं जायेंगे, ऐसा प्रतिबन्ध हम अपने ऊपर डालें, तो मैं मानता हूं कि देश में थोड़ा सा इस तरह का वातावरण बनाने के लिये हम तैयार हैं। लेकिन जब तक सामाजिक वातावरण बनाने के लिये, नैतिक वातावरण बनाने के लिये तथा आध्यात्मिक वातावरण बनाने के लिये हम तैयार नहीं होंगे, हम सिर्फ एक कानून बना कर—और ऐसा कानून बना कर जो कि अव्यावहारिक है—ऐसा वातावरण तैयार नहीं कर सकते।

अब आप मेरा सवाल लीजिये। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मुझे खुशी है, मुझे घमण्ड नहीं है, कई एम० पी० होंगे और शायद वर्धा में भी लोग होंगे, कांग्रेस में भी हैं, जो कि धनवान हैं, लेकिन मेरा व्यक्तिगत खर्च उनसे कम होगा।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : आप कंजूस होंगे।

श्री कमल नयन बजाज : हो सकता है। लेकिन डा० राम मनोहर लोहिया का जो प्रस्ताव है उसमें जो कंजूस हैं वह कम खर्च करे या ज्यादा खर्च करे, इसका सवाल नहीं है। मैं आपकी बात मान सकता हूं कि मैं कंजूस हूं। लेकिन सवाल इस का नहीं है। सवाल यह है कि आज मान लीजिये कि मुझे वर्धा में या देहात में रहना हो और वहीं पर जीवन बिताना हो, तो मेरे लिये 1500 रु० काफी हैं।

एक माननीय सदस्य : तब आप तनख्वाह क्यों लेते हैं ?

श्री कमल नयन बजाज : लेकिन यदि मुझे उद्योगों को बढ़ाना है या इसकी जिम्मेदारी लेकर देश के निर्माण के काम के लिये आगे बढ़ना है और बम्बई में रहना है, तो वहां पर तीन कमरों का फ्लैट का किराया भी आज एक या दो हजार रुपया तक हो जायेगा। जब तक आप इस देश में ऐसी आर्थिक व्यवस्था नहीं कर देंगे कि जिनको तीन बेड रूम्स की जगह मिलनी चाहिये या जितनी भी जगह आप मुनासिब समझते हैं मिलनी जरूरी है, उतनी मिल जाये, और जिसकी कीमत आज 50,000 रु० है वह 2,000 रु० में मिलनी चाहिये, तब तक यह प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा सकता।

डा० लोहिया ने कहा कि मोटर गाड़ियां प्राइवेट हाथों में देना बिल्कुल बन्द कर दिया जाना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यदि यहां की बस सर्विस एफिशिएन्ट हो जाये तो यह बात सोची जा सकती है। एक दफा परन्तु जैसे न्यूयार्क में मोटर गाड़ियों में जा कर जल्दी लोग नहीं पहुंच सकते जितनी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा कर पहुंच सकते हैं। Extremities in a circle are the nearest points. अनडेवेलप्ड कंट्री में अगर गाड़ी का उपयोग नहीं होगा तो न्यूयार्क जैसी सिटी में भी गाड़ी का उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि Life is a circle. और उस में । extremities in a circle are the shortest and nearest points इस तरह की आर्थिक व्यवस्था हमको बनानी पड़ेगी जिसमें वैभव का प्रदर्शन करने वाला

आदमी प्रतिष्ठा न पा सके। ऐसा वातावरण हमको समाज में पैदा करना होगा। आज लोग वैभव का प्रदर्शन क्यों करते हैं। इस लिये करते हैं कि उससे प्रतिष्ठा मिलती है। उसकी हम लोग तारीफ करते हैं, इसलिये वह खर्च करता है, नहीं तो वह कभी खर्च न करे। हम को आज इस बात को ध्यान में रखना होगा कि एफिशेंसी हमारी बढ़े। गाड़ी को हम बन्द कर देंगे तो क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि जो हमारे इंजीनियर हैं, जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनका समय नष्ट होगा आने जाने में, और वे ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे। इस तरह से हमारी एफिशेंसी सुधरेगी, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। एक डाक्टर है, उसको यदि किसी ने बुलाया तो क्या आपका यह ख्याल है कि वह बिना गाड़ी के अच्छा काम कर सकेगा और मरीजों को अच्छी तरह से देख सकेगा। बीस हजार की एक गाड़ी आती है और हजार रुपया उस पर महीने का खर्चा पड़ता है। डिप्रिसिएशन है, ब्याज है, ड्राइवर की पगार है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, टैक्सिस हैं, पैट्रोल का खर्चा है और सब मिला कर आठ सौ से हजार रुपया महीना खर्चा पड़ता है। अगर आप पन्द्रह सौ करें तो ये खर्चे भी तो आप दो सौ रुपये तक लायें।

कराची कांग्रेस के वक्त एक प्रस्ताव आया था। गांधी जी भी उस समय हमारे बीच थे। पांच सौ रुपये सीलिंग करने की व्यवस्था उसमें थी। जैसा कि डाक्टर साहब ने खुद कहा है तब रुपये की कीमत क्या थी और आज क्या है। रुपये की कीमत बहुत कम हो गई है। क्या केवल कीमतों आदि में तीन गुना का ही फर्क पड़ा है या ज्यादा का पड़ा है, यह मैं डाक्टर साहब से पूछना चाहता हूं। वह इसका ज्यादा अच्छी तरह से उत्तर दे सकते हैं।

मैं मानता हूं कि कानून बनाने से यह नहीं हो सकता है। हम कोई इस तरह का प्रस्ताव करें ताकि देश में इस तरह का वातावरण बने जिसमें इस तरह की चीजें न हों और अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कांग्रेस वाले और अपोजीशन वाले बायकाट करें मिल कर। अगर इस तरह का वातावरण समाज में बनाने की कोशिश की जाएगी तो ज्यादा अच्छा होगा।

Shri S. Kandappan (Mettur): Sir, when Dr. Lohia was advancing arguments in favour of his motion, I am certain that at least a few hon. Members of this House were thinking that he is a dreamer. But let us not forget for a moment that the progress of humanity owes much to dreamers also. I am very much in favour of the motion and I support all the sentiments expressed by Dr. Lohia. I think many hon. Members have rather taken too much to what he has said verbatim without reading into the motives and the sentiments behind those arguments. Even the hon. Member who just preceded me said that a doctor who does not possess a car will be in a very awkward position and that Dr. Lohia was suggesting that he should not have a car at his disposal. I am sure Dr. Lohia is definitely not having such things in his mind. At the same time, let us not forget that supposing we do not have these jumbo jets and instead we are in a position not to depend for our foodgrains under PL-480 on America and other countries I am sure that this country would be more happy and its honour more enhanced in foreign countries. That is the spirit with which this motion was moved.

The Government should be really ashamed of calling itself Gandhian. The tragedy is all the more when we see that those people who are the disciples of Gandhiji themselves are indulging in all kinds of ostentatious living, flauting the wealth which is not theirs.

An Hon. Member: Ill gotten.

Shri S. Kandappan: That is quite obvious. But, of course, I would rather be very happy if Shri Morarji Desai, who is considered to be a puritan and one of the closest followers of Gandhiji, in his tenure of office would take some measure to see that this wide gulf that exists in the incomes between the lower strata of society and the upper strata is to some extent bridged. That is the spirit with which this motion was moved. The Government have got enough material for themselves to understand that after independence the poorer sections of this country have become more poor whereas the richer sections have become more rich and richer. That is their statistics. Actually, during the last Lok Sabha, when Dr. Lohia was arguing that the people belonging to the lower strata was getting an income of 3½ annas or so per day, Nandaji, who was the Home Minister then, took strong objection to it and the next day he made a statement and we were amazed and flabbergasted to find that he said that it is 7½ annas and not 3½ annas. If it is 7½ annas, or even if it is one rupee, does it in any way help the poorer sections when the cost of living is so much? So, this government should try to see that some restrictions are put on expenditure.

A Swatantra member asked whether there is any State government with non-Congress parties which has taken any step in this regard. I would like to say in defence of my State that if he chooses to take the trouble of enquiring from his own party members in the Assembly in Tamilnad, I am sure he could get some information as to how the DMK Government, during the short time since it has assumed office, has been able to deliver the goods and satisfy the people to some extent. It is the duty of the Centre to see that there are radical changes made in their fiscal approach and in their basic policies. They should trim the economy in such a way that people belonging to the lower strata of society get something more than what they are getting now.

Here I would like to make one very important suggestion. To my mind, it looks very important. Even in the West European countries, which are considered to be capitalistic, there is some ratio in the income and expenditure of the minimum income group and the maximum income group. Is there any such reasonable ratio in our country between the lowest income group and the highest income group? If we make a comparison in this country I think the ratio will not be one hundred, but one thousand times more. It will not be a reasonable figure. I would like to ask the government this question. Do they not think that the time has come to see that there is at least some ratio fixed for the minimum and maximum income that accrues to the citizens of this country? Let the ratio be 1:10 or 1:20 or even 1:30; I do not mind it. Because, now it is 1,000 times or more, which is very cruel. I would like the government to understand the feelings of the masses in this matter.

Much was said about incentive, profit motive and all that kind of thing. I feel that they are not at all relevant here. What is the feeling, what are the sentiments of the poorer section of the people of this country? They feel that they are orphans in their own land. They are not enthused by the plans. They are not interested in the day-to-day affairs of this country. So, what we need foremost is that we should boost the morale of these people. Actually, there is moral degradation and we are adding insult to injury by allowing increased expenditure for ostentatious living at bureaucratic levels, by allowing private individuals and also government officials to indulge in all kinds of excess living.

So, I am in total agreement with the motion moved by Dr. Lohia. We can alter the figure; that is immaterial. I am sure that Dr. Lohia is not very serious about the figure being

Rs. 1,000 crores or Rs. 500 crores. You should refer it to a committee. Alternatively, you can set up your own committee. Let it go into all the aspects of this problem and let it work out a very justifiable solution, which would be agreeable to the down-trodden masses of this country.

श्री योगेन्द्र शर्मा (बेगुसराय) : जो प्रस्ताव डा० लोहिया ने रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव की जो मूल बात है वह एक ऐसी बात है जिसको भारत की अधिकतर जनता आज से नहीं बल्कि युगों से चाहती आ रही है। और वह भूल जाते हैं, सादगी, स्वदेशी, समता। ये चीजें डा० लोहिया के प्रस्ताव की प्राण हैं। निश्चय ही ऐसी हालत में स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों से हम कोई दूसरी प्रतिक्रिया की आशा नहीं कर सकते थे। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सादगी और स्वदेशी का तिरस्कार करके हम अपने देश के भाग्य का निर्माण कर सकते हैं? यह मूल प्रश्न है और उसके बारे में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। नहीं कर सकते हैं। शासक वर्ग, शासक पार्टी और सरकार से हमारी शिकायत यही है कि जिस सादगी और स्वदेशी का झंडा हमने राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के संग्राम में बुलन्द किया था, उसको उन्होंने तिरस्कृत और लांछित कर दिया--और डालरों की चकाचौंध से प्रभावित होकर देश के भाग्य और भविष्य को अमरीकियों के सामने समर्पित कर दिया।

Shri M. Amersey (Banaskantha): Not only the dollar but also the rouble.

श्री योगेन्द्र शर्मा : अगर माननीय सदस्य को देश की वास्तविकता का कुछ ज्ञान होता, तो वह ऐसी बात न कहते।

आज हमारे देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह आर्थिक विषमता की है। एक तरफ़ ग़रीबी रो रही है और दूसरी तरफ़ अमीरी अट्टहास कर रही है। ग़रीबी और अमीरी के बीच में आर्थिक विषमता की जो बढ़ती हुई खाई है, उसमें न केवल हमारे देश की स्वतन्त्रता, एकता और विकास, बल्कि उसकी आत्मा भी धंसी जा रही है। यदि हमने अपनी स्वतन्त्रता और एकता, अपने प्रजातन्त्र और अपने राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा करनी है, तो हमें इस आर्थिक विषमता का अन्त करना पड़ेगा और उसके लिए हमें फिर सादगी, स्वदेशी और समता का झंडा बुलन्द करना पड़ेगा।

हम डा० लोहिया को बधाई देते हैं कि उन्होंने इस झंडे को बुलन्द किया है, लेकिन साथ साथ हम यह कहना चाहते हैं कि यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है और यह एक ऐसा प्रश्न है, जिसका बहुत ही तीव्र विरोध होगा। वह तीव्र विरोध निहित स्वार्थ वालों की तरफ़ से होगा और हमारे देश में काफी मजबूत निहित स्वार्थ वाले हैं। यदि डा० लोहिया अपने इस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें मजबूती के साथ निहित स्वार्थ वालों के खिलाफ संघर्ष के लिए भी तैयार होना होगा। लेकिन अगर वह यह कोशिश करें कि हम स्वतंत्र पार्टी को भी मिला लें, राजाओं को भी मिला लें, राजमाताओं को भी मिला लें और सब को मिला कर भानुमती का कुनबा खड़ा कर दें, तो उनका यह उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : साम्यवादी दल को भी मिलायेंगे।

श्री योगेन्द्र शर्मा : वह और साम्यवादी तो एक दूसरे के बहुत निकट हैं।

इसके लिए देश की सब प्रगतिशील शक्तियों को एक भीषण संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। हमारे देश के विकास के सामने जो खाई है, उसको पाटने के सम्बन्ध में, हमारे देश की आसन्न समस्या के समाधान के सम्बन्ध में हम एक ऐसी फैसलाकुन जगह पर पहुंच गए हैं, जहां हमें यह निश्चय करना होगा कि आया हम निहित स्वार्थ वालों पर आघात करते या नहीं, अपने यहां की फिजूलखर्ची को बन्द करते

[श्री योगेन्द्र शर्मा]

हैं या नहीं, म्राडम्बर का म्रन्त करते हैं या नहीं ।

जिस देश में सैकड़ों, हजारों म्रादमी दो वक्त खाना न मिलने के कारण मरते हैं, यदि ऐसे देश में म्राडम्बर को बन्द नहीं किया जायेगा, तो क्या वहां पर विद्रोह नहीं होगा ? माननीय सदस्य, श्री वाजपेयी, ने सही कहा है कि यदि इस समस्या का निदान नहीं किया जायेगा, तो देश में विद्रोह होगा । श्रौर यदि देश में विद्रोह होगा, तो स्वतन्त्र पार्टी के सदस्य महोदय को सोचना चाहिए कि उससे किसको घाटा होगा श्रौर किसको फायदा होगा ।

इस सवाल पर भी विचार करना चाहिए कि खर्चे पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ यह भी म्रावश्यक है कि म्रामदनी पर भी प्रतिबन्ध लगाया जाये । म्रगर डा० लोहिया म्रामदनी पर प्रतिबन्ध लगाने की बात नहीं करेंगे, तो स्वतन्त्र पार्टी के सदस्यों को उन पर हमला करने का मौका मिल जायेगा, जैसे कि म्रभी स्वतन्त्र पार्टी के एक माननीय सदस्य ने उन को "सैडिस्टिक" कहा है ।

स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य ने कहा है कि खर्च को नियन्त्रित करने की बात म्रस्वाभाविक है श्रौर भोग की भूख बिल्कुल स्वाभाविक है । यह बात सुन कर हंसी म्राती है । एक जमाना था, जब उनके विचारों के पूर्वज कहते थे कि व्यक्तिगत सम्पत्ति तो कुदरती, ईश्वरीय, चीज है श्रौर समाजवाद मानव स्वभाव के खिलाफ़ है । लेकिन इतिहास ने उनकी सारी बातों को मिट्टी में मिला दिया । हम समझते हैं कि इतिहास से सबक लेते हुए इन भाइयों को सोचना चाहिए कि हमारे देश की परिस्थिति का यह तकाजा है कि म्रार्थिक विषमता का म्रन्त करने के लिए, सादगी श्रौर स्वदेशी को लाने के लिए न केवल खर्चे पर पाबन्दी होनी चाहिए, बल्कि म्रामदनी पर भी पाबन्दी होनी चाहिए, प्रिवी पर्सिज का म्रन्त होना चाहिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए श्रौर इजारेदार लोगों ने मुनाफ़े श्रौर धन तथा सम्पत्ति के केन्द्रीकरण को तोड़ा जाना चाहिए । जब तक यह नहीं किया जाता है, तब तक खर्च पर भी पाबन्दी नहीं लगाई जा सकती है ।

खर्चे पर प्रतिबन्ध कैसे लगाया जाये, इसके बारे में तरह तरह के विचार हो सकते हैं । डा० लोहिया का प्रस्ताव है कि इन सब बातों पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की जानी चाहिए । इसलिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : उपाध्यक्ष महोदय, डा० लोहिया का प्रस्ताव बड़ा सुन्दर, परन्तु एकांगी है । वह सुन्दर इस म्रर्थ में है कि उन्होंने सरकार की मशीनरी श्रौर सरकारी म्रफ़सरों के म्रत्यधिक खर्च पर प्रतिबन्ध लगाने का सुझाव दिया है । इसलिए मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

नेहरू जी के जमाने में डा० लोहिया ने कहा था कि इस देश में 27 करोड़ म्रादमी साढ़े तीन म्राने रोज पर गुजारा करते हैं । उस समय नेहरू जी श्रौर नन्दा जी में इस बारे में कांट्राडिक्शन हो गया । नेहरू जी ने 15 म्राने की फ़िगर बताई श्रौर नन्दा जी ने साढ़े सात म्राने की । मैं गणित का विद्यार्थी हूं । मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि साढ़े तीन म्राने, पन्द्रह म्राने श्रौर साढ़े सात म्राने का श्रौसत चार म्राने हुम्रा । म्राज डा० लोहिया ने म्रपनी बात को करेक्ट किया श्रौर चार म्राने की फ़िगर दी ।

प्रश्न यह है कि जब इस देश के 27 करोड़ म्रादमी चार म्राने रोज पर रह सकते हैं, तो हमारे देश के जो म्रफ़सर श्रौर दूसरे बड़े लोग हैं, क्या वे एक हजार रुपये पर नहीं रह सकते हैं । उनको रहना चाहिए । कांग्रेस पार्टी श्रौर इस गवर्नमेंट ने देश में समाजवादी व्यवस्था लाने का नारा लगाया है । मुझे इस बात की खुशी है कि गांधी जी के साथ काम

करने के नाते डा० लोहिया में भी वह प्रेरणा है। गांधी जी के नेतृत्व में हम सब लोगों ने उसी कैम्प में काम किया था। गांधी जी ने जो अग्नि प्रज्वलित की थी, उसकी चिंगारियां चारों ओर फैली है और उनका प्रतिफल हमारे देश में प्रकट होगा। हमने इस देश में समाजवाद लाना है। हम पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में नहीं हैं। हम समाजवादी व्यवस्था के पक्ष में हैं।

लेकिन मैं वामपन्थियों को कहना चाहता हूं कि वे इस प्रस्ताव के विषय, अर्थात खर्च पर रोक और पूंजी आदि के सावल को एक दूसरे के साथ न मिलायें। अगर एक सवाल होगा तो दूसरा सवाल भी आटोमेटिकली हल हो जायेगा। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन उसका वर्तमान विषय से सम्बन्ध नहीं है। जहां तक समाजवाद में विश्वास का सम्बन्ध है, हम कांग्रेस वाले डा० लोहिया या अन्य वामपंथी लोगों से कमजोर नहीं हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाजवाद में विश्वास करने वाले हम सब लोग आपस में सहयोग करें और आगे बढ़ें।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

Shri P. Ramamurti (Madurai): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was listening to Mr. Kamalnayan Bajaj and I was really wondering why he was advocating today that it is not necessary to put a ceiling on expenditure but that we should really create a climate in this country for putting a ceiling on expenditure. After 20 years of this Congress rule, that somebody should come and plead in this country for creating a climate is itself the biggest damnation of the values they have created in this country during the last 20 years.

My friend, Mr. Somani, was talking about incentives. He said that if this resolution is put into effect, the incentive for investment will go away. I do not know what he is talking about. I do not know whether he has read the resolution at all. It does not even ask for a ceiling on income. It only asks for a ceiling on expenditure. I do not know what this logic is that the more expenditure an individual incurs upon himself, the more investment there will be. I do not understand that kind of logic. Anyway, he was talking about incentives. I really do not know what type of incentives the capitalist class has created in this country during the last 20 years. Who gets the cream of benefit? Have they invested out of their own pockets? They control the banks; they go to the institutions and then there is the foreign investor, the collaborator. What is the wonderful initiative they have taken in this country. I would like to know. They have taken the type of initiative that has been taken by the early industrialists of Great Britain or Germany during the period of developing capitalism. At that time, the proverb was: Honesty is the best policy. I understand that policy. The Britishers did not say, "Honesty is the best virtue" but they said, "Honesty is the best policy". In the

15 hrs.

period of competitive capitalism, it was, "the more honest one is, the more the trade". Therefore, he said, 'honesty is the best policy. But today under the conditions in which we are developing in our country, the more dishonest one is, the more it is paying. That is how our Indian capitalists today are developing. Therefore, to talk of this development, I cannot understand what this incentive is. But at the same time I also know that it is very difficult to enforce such a legislation under the existing set-up. We know, for example, that 95 per cent or even 100 per cent taxation is also there and we know also how much of money comes . . . (*Interruptions*) Yes, 130 per cent taxation may be there, but still the money will not come. We are importing experts on every conceivable thing; even with regard to

[Shri P. Ramamurti]

hotel industry, we want experts. But with regard to one particular industry or profession, India can export to foreign countries any number of experts and that is, tax-dodging, how to cook up double accounts and dodge. In that kind of experts India today has a monopoly. Therefore, I do not know how exactly this Resolution can be or is going to be enforced under the present set-up. Nonetheless, I see no reason why the Congress Party should oppose it. After all, the Congress Party, the Congress members—officially, I am saying—may support it. Mr. Morarji Desai officially will accept it. The whole point is that, after all, the Congress Party very recently passed a Resolution in their All India Congress Committee and Working Committee that they are for a ceiling on income. This is the Resolution which they have adopted. If they have adopted the Resolution asking for a ceiling on income, this Resolution merely asks for an appointment of a Committee to go into the question of the feasibility of working out some scheme by means of which expenditure could be curtailed. It is a very liberal expenditure that Dr. Lohia has allowed, Rs. 1500 per individual. That means, for a family of five, it will be Rs. 7,500. That is what it means. (*Interruptions*) I would only request Dr. Lohia to amend the Resolution properly. It may be interpreted in that way.

Therefore, I do not see any reason why the Congress Party officially should oppose it because, having passed that Resolution on ceiling on income, they should have no objection to the appointment of a Committee of Members of Parliament to go into the question of putting a ceiling on expenditure. After all, this is only asking for the appointment of a Committee. We know what the Congress Party does, what the officials do, in the committees. So many things are referred to committees and then, the committees' reports are shelved. Anyway, let the Committee be appointed. Let them go into the question and make a report and then we shall see what we should do. Therefore, there should not be any objection to accept this Resolution. This should be accepted.

Shri Dinkar Desai (Kanara): I rise to support the motion moved by Dr. Lohia.

My friend, Mr. Somani, of the Swatantra Party said that there would not be any incentive if there was curtailment of expenditure. I am not an economic expert, but I can tell this House that an economic expert from the Cambridge University, Prof. Kaldor, was in this country some years ago and he has submitted a report to the Government of India giving various suggestions on the taxation system, and here, in this report, there is a chapter on Personal Expenditure. He has clearly stated there in that it is very essential in a country like India that the expenditure must be curtailed particularly the expenditure of the well-to-do classes, because he says that in this country the common people are so poor that they cannot save anything. The common man, for instance, in America or in England or in the Western countries saves and that is how capital is accumulated for the development of the country. But in this country the masses are so poor; in fact, they are not only poor but they are hungry; they cannot save anything, and it is only the well-to-do classes that can save. So, it is all the more necessary in this country that there must be a restriction on the expenditure.

I would like to read out one sentence in this connection from Prof. Kaldor's report. It reads thus:

> "As the consumption standards of the masses of the population in India are so near to the bare minimum level the reduction in the propensity to consume of the well-to-do clases appears to me as an indispensable requirement for sustaining a higher rate of economic growth.".

This was written 12 years ago. He had referred to the bare minimum level. But now the masses have reached the hungry level or the starvation level.

The problem of this country is not one of poverty; we accept poverty, but the real problem of India is the problem of hunger. Today, our masses are hungry and they are starving. They see that on the one side there is hunger and on the other there is luxry. Unless this is stopped, I do not think we can make much progress. Not only from the economic point of view but from the social point of view also this matter must be considered.

Any restriction on expenditure has nothing to do with incentives, as my hon. friend Shri P. Ramamurti has already pointed out. If there is a restriction on income, then there may be less incentive, perhaps, but there also I do not agree. But when there is a restriction on expenditure, there cannot to any curb on incentives at all, and if there is any curb on incentives, a man like Prof. Kaldor would not have made that suggestion. He is an economist. I am not an economist. I am a simple man, a layman, speaking from the common man's point of view.

Moreover, there is a psychological reason also why we should have this restriction on expenditure, because psychologically it would be very good because thereby the masses would also feel that there is no luxuy in this country and whatever they produce will ultimately go towards capital formation for the development of the country. That will have a very good psychological effect. Today, there is no such psychological effect because they see on the one side hunger and on the other side luxry and that is why naturally today the common man is not interested in working very hard because he feels that if he works very hard the well-to-do classes and the capitalists will get the benefit. I can assure this House that if the proper psychology is created by restriction on expenditure and the stopping of luxury, our masses will work harder and they will co-operate with the Government and the nation in the Five Year Plans etc.

Finally, I would like to give one warning to this House. If this present state of affairs continues, hunger on the one side and luxury on the other, there will be a violent revolution in this country. Let not the House forget that. This is the lesson of history. What has happened in China may happen here. That is why I request the Deputy Prime Minister to accept this motion. After all, what does the motion ask for? It only suggests the appointment of a committee. The figures given in the motion may not be quite correct. Nobody can say that they are correct. But let Government not refuse to appoint a committee. This is a fundamental question affecting not only our economy but the whole structure of our society.

That is why I strongly commend Dr. Ram Manohar Lohia's motion for the acceptance of this House.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, डाक्टर लोहिया साहब ने जो तहरीक शुरू की उस पर मुझे इकबाल का एक शेर याद आ गया :

ऐ के तुझ को खा गया सरमायदार है लागर,
शाखे आहू पर रही सदियों तलक तेरी बारात,
मक्र की चालों से बाजी ले गया सरमायेदार,
इन्तहाये सादगी से खा गया मजदूर मात ।
—इकबाल ।

मैं डा० लोहिया की जो तहरीक है, उसके लिये उनको मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरी तरह से मुबारकबाद पेश करता हूं । पहली बार इस सारे हाउस में उन्होंने पते की बात कही है । मैं एक नया मेम्बर हूं और जब से आया हूं कभी मैंने डाक्टर साहब को डा० तेजा में उलझते देखा, कभी वह स्वेतलाना से उलझ जाते हैं, कभी ऐसी बातें कह देते हैं जो उनके

[श्री रणधीर सिंह]

मयार से कम होती है । मैं डा० लोहिया की इस देश के बड़े बड़े कांग्रेसी ने ताओं जैसी इज्जत करता हूं, उतनी ही इज्जत करता हू, बड़े दिमागदार आदमी हैं । पहली बार उनकी तरफ़ से एक ऐसी नौयत की बात आई है जो देश में इन्कलाब का असर रखती है, जो देश में एक सोशल चेंज, एक सोशल जस्टिस की शक्ल लेकर रूनुमा होती है । मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह बात कह कर उन्होंने न सिर्फ हमें बेदार किया है, बल्कि मुल्क की एक सेवा की है और वह यह कि इनका असल मुद्दा यह है कि हर घर में चिराग जले, हर पेट में रोटी जाय, हर जिस्म पर कपड़ा हो, कोई अनपढ़ न हो, कोई बीमार न हो, हर गांव में सड़क जाये, हर गांव में बिजली हो, हर किसान के खेत में पानी पहुंचे और हमारा देश एक आला मैयारे-जिन्दगी हासिल कर सके । यह सोशल चेंज की बात है और मैं एक सोशलिस्ट होने के नाते, कांग्रेसी सोशलिस्ट होने के नाते इसका स्वागत करता हूं ।

लेकिन एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहूंगा कि इन्होंने जितनी बातें कही हैं, उनमें बहुत सी इम्प्रेक्टिकल बातें कह गये हैं । जैसे इन्होंने कह दिया कि गवर्नमेंट एम्पलाइज 30–40 लाख सरप्लस हैं, आप तो दो-दो आदमियों के पीछे लाठी लिये फिरते हैं, अगर 30–40 लाख को घर भेज दिया तो डा० लोहिया क्या करेंगे । ये बातें युटोपियन हैं । मैं ज्यादा लम्बी बात में नहीं जाना चाहता और यह कहना चाहता हूं कि आज जितना भी तरक्की पसन्द ग्रुप है, सारी कांग्रेस इस सोशल चेंज को लाना चाहती है, तो फिर वह अपना वक्त उधर क्यों खराब कर रहे हैं, इस तरफ आकर, उन बेंचेज पर नहीं, अपने ब्लाक समेत इधर आइये, और यह जो अपना रेजोल्युशन है इसको अमली तौर पर गवर्नमेंट के साथ मिल कर पूरी तरह से कामयाब बनाइये, इस तरह से देश आपके आला दिमाग से फायदा उठायेगा । बस मैं यही कहना चाहता हूं ।

Shri Tenneti Viswanatham (Visakhapatnam): I will start by saying उपाध्यक्ष महोदय,

Sir, until I heard the young member from the Swatantra Party, I did not like to intervene in this debate. When he spoke on a previous occasion, I thought he was one of those few young men here who were shaping very well, but today I find he has used choice expressions against a fellow member, expressions which cannot be imitated by anybody; nor is it worthwhile for me to repeat them. But I can say this that the language he has used is the very language which is the result of accumulation of wealth. Because there is excess of money, there is excess in language also. That is what has been proved today.

After all, what has Dr. Lohia said? As some friends have already pointed out, he says: put a limit on the expenditure. If there are no immediate methods by which we can do it, a committee might consider it. There was the expenditure tax. Was it considered practicable? The Expenditure Tax Act was unanimously passed by the Lok Sabha. You thought there was some method of doing it. You experimented with it. A tax on expenditure after Rs. 1500, even a cent per cent tax over and above that, is not at all difficult. If you put Dr. Lohia and me there for two days, we will do it, there is absolutely no difficulty in that, but all that I would say is that, as some friends have warned, we should see the atmosphere in the country in which we are living. Rs. 1,500 of expenditure for an individual—what a huge sum! When the average *per capita* income is Rs. 330 or Rs. 380, I thought he would not go so far, having come from Rajputana, I thought he would put it very low, but he has put it at Rs. 1,500. Who are the persons in India today who are able to spend Rs. 1,500 a month on themselves? They are only exploiters. Excepting exploiters, others have not

got so much money to spend. Probably they may be a few lakhs, that is all. Therefore the whole argument against the motion is in favour of a few lakhs, and the whole complaint is that the few lakhs are exploiting the entire nation. The foreign exploiters went away and others have stepped into their shoes. It is to prevent that that a social revolution in thought is going on in this country, and I do submit in all humility that this resolution should be accepted as a gesture, as a concession to the rising forces in this country. Otherwise, something else may happen which you and I do not like, although a few in this country may like. It is very necessary that we should adapt ourselves to changing situations, and Rs. 1,500 of expenditure a month is a very high limit, and I think the excess over it can be taxed, or otherwise mopped up. When it goes into the hands of Government, again they have got their own method of spending it, but we are willing to give it into the hands of the Government. Therefore, I appeal to the Government and the Congress Party to accept this.

Shri J. B. Kripalani (Guna): I am often in agreement with Dr. Lohia, and on this occasion I am sorry to say that I am against the appointment of this committee. Who knows they might accept his proposition, and it is a very dangerous propostion. It is also a very irreligious proposition.

How do the rich get their money? In India, if they paid taxes and if they did not indulge in blackmarketing, they will have no wealth at all, because as Mr. Piloo Masani says they have to pay 130 per cent taxes.

An Hon. Member: Piloo Mody.

Shri J. B. Kripalani: They belong to the same stock. So, it does not matter.

When they get their money like this, they will, I am sure, hereafter burn in hell fire, because rightly Christ had said that it is more difficult for the rich to go to Heaven than it is for a camel to pass through the eye of the needle.

Shri M. R. Krishna (Peddapalli): It is easier for the camel.

Shri J. B. Kripalani: Do we want these rich people who have amassed their wealth by *anyaya* means to go to Heaven? Let them stew in their own juice.

An hon. Member: They do not want Heaven.

Shri J. B. Kripalani: Then you do, not believe in your own religion, you do not believe in Christ, you do not believe in every religion which says that the poor shall inherit Heaven, the rich shall inherit only this earth which is transitory. Why don't you allow them to burn in hell fire eternally and always?

An hon. Member: What a cruel man!

Shri J. B. Kripalani: And then, Christ has also said that the kingdom of Heaven shall belong to the poor and not to the rich; also, our scriptures say that riches are a danger, and so I really do not understand why Dr. Lohia does not allow the rich to grow richer and the poor to grow poorer as is being done in this country by this blessed Government. I congratulate the Government because I have found that whenever. I am in difficulty, I begin to pray to God; when our people are starving, they will pray to God; the rich people never pray to God; they do not pray even to the devil; they are not afraid of God; neither are they afraid of the devil; so let them hereafter be damned eternally! Therefore, why do we want to stand in the way of their suffering? I think it is very unreasonable.

It is good that the Congress Government is trying to make the rich richer so that they may go positively to hell, according to Christ and our scriptures. I remember a story of a sadhu. He felt very hungry and he passed by a garden and there he found that the skins of the melon were left there. He was hungry and he took the skin of the melon and began to eat there. Then the gardener appeared

[Shri J. B. Kripalani]

and he gave him a good beating. Then he said:

"खाली खल जब हमने खाई उस में तो हम मारे गये अगर कहीं हम सब्सटेंस खाते तो पता नहीं क्या होता ?"

So, we must understand this proposition properly and we must not stand in the way of the accumulation and in the expenditure of wealth by the rich because for those who do these things, it will be as difficult to go to Heaven as it is for the camel to pass through the eye of a needle. And let us be poor so that we may remember God in our difficulty and be religious people; and as this land is ours is a religious land, I think poverty is the best remedy for this country.

I am not afraid of any revolution happening, because the people are poor. 30 lakhs of people died in one city of Calcutta in a couple of months and the shops were full of eatables and the godowns were full of grain; yet, even when they were dying, they did not lift their hands; they did not rob; they did not commit murder; they died. Such are our people. How do you expect them, because of their poverty, that they will be so perverse as to create a revolution? Be sure they will never create any revolution, because we have suppressed them so that they have not the capacity of being jealous. In Europe, people are jealous and they create socialism and communism. In this land, we have so suppressed the people; we have kept them so poor that they do not feel jealous. They have no power to resist even. They will die, but they will not touch what they think does not belong to them. They are so religious, so happy, so contented. Why do you want to disturb them?

I am against any committee being appointed as is proposed by Dr. Lohia. They may, who knows, accept this proposition and this country could become a very rich country. And what happens in the rich countries? You can see that in Scandinavia there are more divorces, there are more murders, etc., etc., (*Interruption*). Therefore, let there be more and more expenditure, let the rich spend more and more, and deserve hell.

उपप्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव डा० राम मनोहर लोहिया ने रखा है वह तो उन्होंने जनरल बजट की सामान्य चर्चा के दौरान फरमाया था और आज फिर उसी को अपने प्रस्ताव में फ़रमाया है । तभी तो मैंने कहा था कि उनकी वह बात ठीक नहीं है :

"Dr. Lohia said if you curtail all salaries and all expenditure to Rs. 1500 per month, Rs. 1000 crores will be saved. I do not know where from he got his figures. If you do that, you will be saving only Rs. 25 crores and nothing more."

उसी समय डा० राम मनोहर लोहिया ने मुझे टोक कर बीच में सवाल पूछा और उन्होंने कहा कि यह बिलकुल गलत बात है । तब मैंने कहा था कि अगर डा० साहब की इच्छा हो तो मैं उनके साथ इस पर चर्चा करने के लिए राजी हूं । अगर मेरी बात गलत हो तो मैं समझने के लिये भी राजी हूं । इसी हिसाब से यह प्रस्ताव आज ले आये हैं मैं तो आशा करता था कि वह मेरे साथ चर्चा करेंगे और मुझे कुछ सिखायेंगे । मगर ऐसी चर्चा करने का उनको ज्यादा शौक है

एक माननीय सदस्य : क्योंकि जनतन्त्र है ।

श्री मोरारजी देसाई : आज यहां आये । जनतन्त्र है मैंने मान लिया । मैं ने कोई ना नहीं कहा । जनतन्त्र को जितना मैं मानता हूं उतना डा० साहब नहीं मानते हैं क्योंकि उतना वह मानते तो कभी जितनी दखल वह यहां करते हैं उतनी दखल करते नहीं ।

श्री रबि राय (पुरी) : दखल देना भी प्रजातन्त्र है ।

श्री मोरारजी देसाई : ठीक है वह भी उस तरीके से करना चाहिए अपने तरीके से नहीं । उसका भी विधान है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब सोमवार को आप से तरीका सीखने के लिये आयेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : मैं कोई तरीक़ा सिखा नहीं सकता । मैं कभी आपको सिखा नहीं सकता । इतनी जुर्रत मेरे पास है नहीं और मूर्खता भी नहीं है ।

अब डा० साहब की जो भावना है जो आदर्श है उसके साथ मैं बिलकुल सहमत हूं । इस देश में फिज़ूलखर्ची न हो, इस देश में हर एक को पूरा पूरा खाना मिले, कपड़ा मिले, घर रहने को मिले, शिक्षा मिले ताकि हर एक आदमी अच्छी जिंदगी बसर कर सके । मैं भी यह चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके व्यवहार के लिहाज़ से जितनी जल्दी सम्भव हो, इस देश में किसी के पास भी बड़ी पूंजी न रहे और हर एक को कम से कम अच्छी रिहायश के लिए जितने साधन मिलने चाहिएं काम करने के साथ उतने उन का मिलने चाहिएं । ऐसी हालत मैं देखना चाहता हूं । अगर उस का तरीक़ा डा० साहब ने बताया होता तो जरूर मैं कबूल करता । मूझे कोई उस में ना नहीं होती क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह हो मगर इस तरीक़े से हो नहीं सकता है । डा० साहब को लगता है कि होता है । मुझे लगता है कि नहीं होता है । हो सकता है कि मेरी समझ बहुत अच्छी हो और मैं बहुत दूर तक न देख सकता हूं जितनी दूर कि वह देख सकते हों । परन्तु आखिर तो मुझे जो सूझता है मैं वही तो कर सकता हूं । यहां बैठ करके । उस से ज्यादा तो मैं नहीं कर सकता । मैं उन के दिमाग़ से काम चलाऊं तो मेरे जैसा बेवकूफ़ कौन बनेगा ? अगर मेरे हिसाब से वह चलेंगे तो वह भी बेवकूफ़ बनेंगे । इसलिए हर एक को दूसरे की अक़ल का फ़ायदा उठाना चाहिए मगर उस अकल को लेकर तो नहीं चलना चाहिए वह तो अपनी अकल से ही चलना चाहिए । इसलिए मैं कहता हूं, बड़े अदब के साथ कहता हूं, मैं कोई मज़ाक नहीं करता क्योंकि मज़ाक करने का सवाल नहीं है । जिस भावना और जिस आदर्श को लेकर वह प्रस्ताव लाये हैं मैं उस का कभी मज़ाक नहीं कर सकता क्योंकि वह भावना बहुत ही ऊंची है और मैं उसे मानता भी हूं मगर मैं सिर्फ ख़याली दुनिया में नहीं जाता । ख़याली दुनिया, ख़याली पुलाव भी खिलाने की बात मैं नहीं मानता । ख़याली पुलाव पकाने के लिए मुझे कोई कहे कि किसी के सुपुर्द करूं तो मैं कैसे कर सकता हूं ? ऐसे ही एक कमेटी बनाने का काम है । इस लिये मैं उसे कैसे कबूल करूं ? उस में कुछ अच्छा निकल सकता है ऐसा लगे तो मैं जरूर करूं ।

हां हमारे बुजुर्ग कृपलानी जी ने अपनी अनोखी शैली में जो कहना था वह कहा, जितनी गालियां देनी थीं इस राज्य को, वह दीं । क्योंकि वह चाहते थे । दिया । उस से मुझे कोई नाराजी नहीं है, क्योंकि यह तो हर रोज सुनने में आती हैं । और अगर इस से मैं उन को खुश कर सकता हूं कि उन की बात मान लू, तो क्यों न करूं ? उन्होंने कहा कि कमेटी नहीं बनानी चाहिये । इस से वह खुश होंगे इस लिए मैं स्वीकार कर लेता हूं । फिर उन का इरादा कोई भी क्यों न हो । उन का इरादा मुझे कहीं भेजने का हो, दोजख में भेजने का हो या जहन्नुम में भेजने का हो, जहां भी भेजना हो, लेकिन अगर इस से उन को खुशी होती है तो मैं खुशी से चला जाऊंगा । इस में मुझे कोई नाराजी नहीं ।

श्री जे० भा० कृपालानी : आप तो साहूकार नहीं हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : राज्य नहीं करना चाहता है। साहूकार का सवाल नहीं है। राज्य ऐसी हालत नहीं रखना चाहता है।

डा० राम मनोहर लोहिया : कहने पर क्यों जाओ, अच्छा है वैसे ही जाओ।

श्री मोरारजी देसाई : वैसे जहां जाना है वहां जाऊंगा। आप की मर्जी क्यों ढूंढूंगा? आप की सरदारी जिन्होंने मानी है वह जायेंगे जहां जाना होगा, मैं क्यों जाऊं उन के कहने से? (व्यवधान) मैं तो चाहता हूं कि सब स्वर्ग जायें। मैं नहीं चाहता कि कोई नर्क में जाये। मैं क्यों चाहूंगा?

Shri J. B. Kripalani: Do we want that the Finance Minister would go to hell. I did not think he was a rich man. I was only talking of the rich men, the capitalists who collect money by unlawful means.

श्री मोरारजी देसाई : हो सकता है कि मैं न समझा होऊं। मैं कबूल करता हूं, मैं उन की बात माने लेता हूं कि उन का इरादा नहीं था। उन्होंने मेरे लिये नहीं कहा था, कांग्रेस के लिये कहा, राज्य के लिये कहा, जो राज्य चलाते हैं उन के लिये कहा। मैं भी तो उस का हिस्सा हूं। मैं उस में आ जाता हूं। मैं इस से कैसे इन्कार करूं?

श्री जी० भा० कृपालानी : कांग्रेस को भी मैंने नहीं कहा। मैं ने पूंजीपतियों को कहा। मैं तो सोमानी और मोदी को कह रहा था।

श्री मोरारजी देसाई : इस में कोई शक नहीं है कि अगर दोनों में कोई पसन्द करना हो, स्वर्ग में गरीबी मिलती हो और दोजख में पैसा मिलता हो तो यह सब भाई दोजख पसन्द करेंगे। वह कभी स्वर्ग पसन्द नहीं करेंगे। इस को मैं जानता हूं, मैं इस से इन्कार नहीं कर सकता। मगर मुझे कबूल है कि आखिर उन्हें जो पसन्द करना हो वह कर लें। इस में मैं क्यों झगड़ा करूं? हमें क्या करना है हमें यह देखना चाहिये।

हम चाहते हैं कि इस देश में हमारा समाज ऐसा बने जिस में ऐसी हालत न हो, फिजूलखर्ची न हो, वैभव का प्रदर्शन न हो। यह मैं जरूर चाहता हूं। मगर जिस तरीके से कहा गया उस तरीके से कैसे होगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इसलिए मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि मैं क्यों ऐसा मानता हूं। पहले तो प्रस्ताव में कहा गया, जिसके लिए श्री राममूर्ति ने कहा था कि यह व्यक्तिगत मासिक आय है जो कि 1500 रु० होनी चाहिए या कि एक कुटुम्ब की। अगर व्यक्तिगत आय है तब तो कुटुम्ब की आय बहुत ज्यादा हो जाती है। मैं मानता हूं कि कुटुम्ब के लिये कहा गया है। एक व्यक्ति के लिये नहीं कहा गया। प्रति कुटुम्ब 18 हजार रुपया सालाना होना चाहिये, ऐसा डा० लोहिया का मन्तव्य है।

श्री रबी राय : यह तो आप मान लीजिये।

श्री मोरारजी देसाई : वह मैं क्यों मानूंगा। वह तो कभी भी नहीं करना चाहिये। अगर आप मान सकते हैं, आपकी अक्ल वहां जाये तो मैं क्या करूंगा? मैं आप की अक्ल दुरुस्त नहीं करना चाहता। रखिये जो आपके पास पड़ी है।

श्री रबी राय : आप भी थोड़ी सी ले लीजिये।

श्री मोरारजी देसाई : मैं ले लूंगा तो फिर आपके पास कुछ नहीं रह जायगा।

श्री रबी राय : हम देते रहेंगे।

एक माननीय सदस्य : आप विषय पर बोलिये।

श्री मोरारजी देसाई : विषय पर ही बोल रहा हूं। जो वह कह रहे हैं उसका

जवाब दे रहा हूं नहीं तो न बोलें। जो बोलेगा उसको जवाब मिलेगा।

अब सवाल यह है कि कितने लोग हैं जिनसे एक हजार करोड़ रुपया मिल सकेगा, जैसा कि डा० लोहिया ने कहा ? हमारे यहां 26 लाख लोग आयकर देते हैं और उन में से 25 लाख लोगों की आमदनी 40 हजार से नीचे हैं। जिसकी 40 हजार की आमदनी है उसके पास 18,000 रु० खर्च के लिये रह जाता है। इतना उसके पास रहता है इसलिये 40,000 कहता हूं। जो बाकी रह जाते हैं उन में 30,000 कम्पनियां हैं और 23 हजार फर्मे हैं। बाकी 22,700 लोग रह जाते हैं। उन में से करीब 20,000 लोग ऐसे हैं जिनकी आमदनी 40,000 और 1 लाख के बीच में है। 1 लाख की आमदनी से ऊपर के लोग 2700 हैं। इतने लोग हैं जिनके पास 18,000 रु० छोड़ कर बाकी पैसा ले लिया जाये तो 1,000 करोड़ कहां से मिलेगा यह मेरी समझ में नहीं आता। आज हम 1 लाख से ऊपर की आमदनी वालों के पास लाख पीछे सिर्फ, 8,000 रु० ही तो रखते हैं, बाकी सारा ले लेते हैं। इसलिये जो मिलेगा वह 8,000 ही तो मिलेगा। इससे ज्यादा लेना चाहें तो भी ज्यादा तो मिल नहीं सकता। यह सारा हिसाब निकालने के बाद अगर गणित शास्त्र के हिसाब से मिलाया जाये तो 40,000 और 1 लाख की आमदनी के बीच के जो लोग हैं उनके पास 18,000 छोड़ कर बाकी सारा ले लिया जाये तो जो लेते हैं उस से ज्यादा से ज्यादा 34 करोड़ रुपया और मिलेगा बाकी जो 2700 लोग रहे उन से 15 करोड़ से ज्यादा नहीं मिलता। इस तरह से कुल मिला कर 50 करोड़ भी पूरा नहीं निकलता। डा० लोहिया ने 1,000 करोड़ कहा। इतना ही नहीं कहा, यह भी कहा कि शायद यह कम बतला रहा हूं हो सकता है 1500 करोड़ मिल जाये।

मगर यह तो सिर्फ जो लोग आय कर देते हैं उन का हिसाब हुआ। कुछ काश्तकार भी ऐसे होंगे जिन की आमदनी इतनी हो, हालांकि ऐसे बहुत लोग हैं नहीं काश्तकार जिन की आमदनी 40,000 से ज्यादा हो। बहुत थोड़े होंगे। मैं नहीं जानता कि उन से 2 या 4 करोड़ रु० से ज्यादा मिल सकता है, अगर मिले भी तो। मगर कहां 1,000 करोड़ और कहां यह राशि। ऐसा समझें कि यह मिल जायेगा तब भी इतना ही होता है। अगर ज्यादा हो सकता है तो हम जरूर लेंगे।

फिर 36 हजार रु० के खर्च के ऊपर यहां एक एक्स्पेन्डिचर टैक्स भी लगाया गया था। पहले लगाया गया, फिर निकाला गया, फिर लगाया गया, फिर निकाला गया। क्यों निकाला गया। इस लिये कि इस में और भी ज्यादा चोरी बढ़ती गई। किसी का फायदा हुआ नहीं। जिस समाज में हम रहते हैं, उस में ही हमें रहना है। उस को हम एकदम से फरिशता नहीं बना सकते। उस को और भी खराब करना राज्य या समाज का काम नहीं है। इसलिये इसके दूसरे रास्ते ढूढने चाहियें, और दूसरे रास्ते हैं। नहीं हैं, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। लेकिन एकदम से वह रास्ता लाने से काम नहीं चलता। उस मे ऊपर भी हमें देखना होगा। नहीं देखना होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मगर इस तरीके से यह काम करने से काम होगा नहीं।

बाकी बात रही इन्सेन्टिव की। हमारे जवान संसद सदस्य श्री सोमानी ने जो कहा उस को मैं पसन्द जरूर नहीं करता। जिस भाषा में उन्होंने कहा, वह अच्छी नहीं थी क्योंकि इस तरीके से कहने से कोई फायदा नहीं होता। मगर वह इस लिये कहते है मानो उन को अपना ही बचाव करना है। इस में से उनको लगा कि कहीं अगर ऐसा हो ही गया तो क्या होगा। एक दिन तो होना ही है। यानी इस तरह की आमदनी

[श्री मोरारजी देसाई]

और इस तरह की पूजा रहेगी नहीं, ऐसा मैं मानता हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप सब की आमदनी बढ़ाने की चेष्टा करें ।

श्री मोरारजी देसाई : आमदनी बढ़ानी है, लेकिन जो लोग भूखे मरते हैं उन की आमदनी पहले बढ़ानी होगी । आज जो इन्सेंटिव देना है वह इसीलिये देना है, क्योंकि बराबरी नहीं है । आखिर कुछ पैसा उन के पास भी रहना चाहिये, उन्हें भी कमाना है और हमें उन से टैक्स लेना है । अगर 100 फीसदी उन से हम टैक्स ले लेंगे तो कोई कमायेगा क्या ? कोई भी सन्यासी नहीं है । सन्यासी किसी को हम बना भी नहीं सकते । यहां डा० लोहिया भी सन्यासी नहीं बने हुए हैं । वह कहते हैं कि हमारे उपनिषद्कारों ने, ऋषियों और मुनियों ने हमें भोग का संयम सिखाया । मार्क्स ने भी सम्पत्ति का संयम सिखाया । कितने लोग सीखे यह मैं पूछना चाहता हूं ?

डा० राम मनोहर लोहिया : दोनों मिलाओ तब काम चलेगा ।

श्री मोरारजी देसाई : एक से नहीं सीखा है तो दोनों से कहां सीखेंगे । . . .

डाक्टर साहब बड़े महत्वाकांक्षी हो सकते हैं, वह बहुत ऊंचा उठने की लालसा रख सकते हैं, वह इतने बड़े होना चाह सकते हैं कि पैगम्बर बन जाएं । वह बड़े बनें, मैं बहुत राजी होऊंगा । . . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं नाचीज हूं, रास्ता सिर्फ दिखा रहा हूं . . .

श्री मोरारजी देसाई : बड़े लोग जो होते हैं वे अपने आप को नाचीज ही मानते हैं । यह उनकी नम्रता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : यह क्या हमेशा पैगम्बर बनने की बात कहा करते हो ?

श्री मोरारजी देसाई : पैगम्बर बनेंगे तो मैं आपकी पूजा करूंगा । लेकिन आज आप नहीं हैं ।

श्री मधु लिमये : आप बनें ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं पैगम्बर बनूं । डा० साहब क्रांतिकारी बनना चाहते हैं, यह मैं समझ लेता हूं, यह मैं कह देता हूं ? नया कायदा लाना चाहते हैं, नई चीज लाना चाहते हैं, यही मैं मान लेता हूं । शब्दों के साथ क्यों झगड़ा करते हैं । मैंने कोई अपमान करने की नीयत से नहीं कहा था । मैं कहता हूं कि वह महत्वाकांक्षी हैं और जरूर हैं । नई दुनिया बनाना वह चाहते हैं और ऐसी नई दुनिया जिसके बारे में कोई और नहीं सोचता है । जरूर नई दुनिया वह बनायें । मैं मना नहीं करता हूं । लेकिन इस तरीके से वह कभी नहीं बनेगी । इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शक्ति उन में है उसको वह ऐसे कामों में लगायें जो व्यावहारिक काम हैं । ख्वाबों की दुनिया में वह न रहें । व्यावहारिक वह बनें तो ज्यादा फायदा होगा और उनकी शक्ति का सदुपयोग भी होगा । यही मेरा कहना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है ।

प्रेरणा की बात भी यहां कही गई है । हम चाहते हैं कि हम फिजूलखर्ची को कम कर सकें और भोग पर संयम लगे । लेकिन मैं पूछता हूं कि कौन भोग से बचा है, डाक्टर साहब बचे हैं या मैं बचा हूं, कौन बचा है । हम सब पर यह चीज लागू होती है । लेकिन सौ चूहे खा कर बिल्ली हज को चली वाली बात नहीं होनी चाहिये । ऐसी बातें करने से काम नहीं होता है । जब हमारी यह अवस्था है तो हम दूसरों के पास जा

कर उन से सयम नहीं करवा सकते हैं । भोग पर संयम लगवाना चाहते हैं, जरूर लगवायें । महात्मा गांधी ने भी कई लोगों से यह करवाना चाहा था । लेकिन बहुत कम लोगों ने किया था । यही दुनिया की तारीख है । संयम करेंगे तो लोग अपने आप करेंगे । जबर्दस्ती आप नहीं करवा सकते हैं । समाज में यह ठीक है कि कानून की भी जरूरत होती है । कानून से कुछ हो भी सकता है । लेकिन जितना वह समझते हैं कि कानून की सहायता से हो सकता है उतना नहीं हो सकता है ।

आखिर आदमी पैसा कमाता है तो खर्च करना भी चाहेगा । खर्च करना नहीं चाहेगा ऐसी बात नहीं है । पैसा वह अपने परिवार के लिए रखना भी चाहेगा, देने के लिए भी पैसा कमाना चाहेगा । खैरात देने के लिए भी वह पैसा चाहता है जिससे उसका बड़प्पन जाहिर हो, उसका नाम हो । सारा अपने ऊपर ही खर्च करना वह चाहेगा, यह भी हो सकता है । पैसा वह कमाये उसको वह खर्च करना चाहिये अपने पर और अपने बच्चों पर और उसको आप रोकना चाहें तो रोक सकते हैं लेकिन इस तरह से न रोकें कि वह काम करना भी बन्द कर दे, काम भी रुक जाए, और सम्पत्ति पैदा ही न हो । जब सम्पत्ति पैदा ही नहीं होगी तो क्या बांटेंगे, इसको भी तो सोचना चाहिये ।

डाक्टर साहब ने कहा कि एक करोड़ सरकारी नौकर हैं । जरूर हैं । लेकिन एक करोड़ में से अठारह हजार के ऊपर आमदनी वाले कितने लोग हैं ? मैं मानता हूं कि दस हजार नहीं तो बारह हजार होंगे । इससे अधिक नहीं हैं . .

Shri M. Amersey (Banaskantha): What about bribery and corruption?

श्री मोरारजी देसाई : जो देने वाले लोग हैं उन से इसके बारे में पूछिये । उनको कहिये ।

Shri M. Amersey: Your law makes it so.

श्री मोरारजी देसाई : कानून तो है लेकिन कानून करप्ट नहीं करता है । जो कानून तोड़ने वाले हैं वे ही ऐसा कहते हैं । जो लोग लोकशाही को मानते हैं उन का फर्ज है कि वे कानून को कैसा भी वह हो, मानें और उसको तोड़ना हो तो खुले तौर से तोड़ें और सजा को सहन करें । चोरी से काम अगर होता है, चोरी से अगर पैसा पैदा किया जाता है तो उसको कोई बरदाशत नहीं करेगा । यह कहा जाता है कि चोर नहीं पकड़े जाते हैं । पकड़े गए तो चोर, नहीं पकड़े गए तो साहूकार । लेकिन एक न एक दिन तो पकड़े ही जाते हैं । नहीं पकड़े जाते हैं ऐसी बात नहीं है । समाज और राज्य का काम है कि इनको ठीक करे । ठीक करने के लिए हमें ठीक तरीके से इंतजाम करना पड़ेगा । कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा । उस में से कुछ नहीं निकलेगा । एक मोनोपोली कमिशन बना था पांच साल हो गए अभी भी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : तनख्वाह खाते हैं ।

श्री मोरारजी देसाई : तनख्वाह खाने की बात नहीं है । तनख्वाह आप पाते हैं, वे नहीं । तनख्वाह का काम आपके सुपुर्द कर दिया है । इसी लिए आप काम करते हैं, वे नहीं . . .

Shri Piloo Mody: Don't reply to me in Hindi. I can speak in Hindi but I do not understand it.

श्री मोरारजी देसाई : यही सवाल है कि बोल सकते हैं लेकिन समझ नहीं सकते हैं । वही डाक्टर लोहिया कहते हैं । दुरुस्त

[श्री मोरारजी देसाई]

करना चाहते हैं लेकिन ये दुरुस्त नहीं होते हैं । पास बैठ कर वह भी देखते हैं फिर भी मुझे कहते हैं कि कमेटी मान लो । कसे मानूं इसीलिए कमेटी की बात नहीं मान सकता हूं ।

मैंने पहले कहा है कि ख्वाबी पुलाव पकाने के लिए मैं किसी को भी नहीं कहूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मुझे खुशी है कि तीन हफ्ते मे वित्त मंत्री जी पच्चीस करोड़ से पच्चास करोड़ तक पहुंचे । जब पहले बोले थे तब कहा था कि सिर्फ पच्चीस करोड़ बचेंगे । आज बोले तो कहते हैं कि पचास साठ करोड़ बचेंगे । इस रफ्तार से चलते रहे तो छः महीने में मेरी जगह पर पहुंच जायेंगे ।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पचास करोड़ । लेकिन आप उसको पकड़ न लें । यह सब कुछ किया जाए तो शायद हो सकता है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अब कभी गर्दन आपकी पकड़ में आ जाए तो चिल्लाया कम करो । गर्दन पकड़ी गई है इस वक्त थोड़ी सी आपकी । इस लिए मैं बता रहा हूं कि पचास करोड़ पर आज आप पहुंचे हैं और सोमवार को जब आपकी और हमारी बात होगी तो शायद तीन सौ करोड़ तक पहुंच जाओगे मैं हजार डेढ़ हजार करोड़ कहना चाहता हूं । मैं सब आंकड़े दे चुका हूं । अब मैं ज्यादा वक्त खराब करना नहीं चाहता हूं ।

मैं खाली एक बात कहना चाहता हूं । यह बात मैं राममूर्ति जी को और शर्मा जी को कहना चाहता हूं । मैंने जानबूझ कर खर्चा कम करने को कहा है । इसलिए कहा है कि बहुत से नौकरशाह और मंत्री लोग तनख्वाह पाते हैं तीन हजार चार हजार रुपया महीने की लेकिन सुविधायें उनकी होती हैं दस हजार, पचास हजार, अस्सी हजार और एक लाख रुपये की । आप अच्छी तरह से समझ लो कि जब मैं खर्चा कहता हूं तो मेरा मतलब तनख्वाह और सुविधाओं दोनों से है । हमारा भारत सुविधाओं का देश है । संसार में सर्व श्रेष्ट सुविधाओं का देश है । मैंने अपनी सुविधायें खुद गिनाई हैं । मैं जानता हूं कि सुविधायें आसानी से नहीं छोड़ी जा सकती हैं । विधि और कानून पास हो जाएगा तो ये सुविधायें हम सब को छोड़नी पड़ेंगी । इसलिए खर्चे के मामले में बात साफ हो जानी चाहिये । मेरा मतलब सुविधाओं से है तनख्वाह से है । और जिन लोगों ने यहां पर कहा है कि आमदनी के ऊपर अंकुश तो बिल्कुल साफ बात है कि जो डेढ़ सौ रुपये मिलना है वह कुटुम्ब पीछे मिलेगा व्यक्ति के पीछे नहीं । यह राशि कुटुम्ब के पीछे खर्च करने को मिलेगी । इससे कोई तिजौरियां नहीं भरती जायेंगी । मैंने पहले ही भाषण में कह दिया था कि ज्यादा से ज्यादा सन्तान वगैरह की प्रेरणा के लिए एक आदमी को पांच सौ रुपया या हजार रुपया महीना दे दिया करो तो अलग बात है । इसका साफ मतलब होता है कि आमदनी करके अप्रत्यक्ष रूप से अपने पास रखने की इस प्रस्ताव में कोई गुंजाइश नहीं है ।

हमारे कम्यूनिस्ट भाई समझने में गलती न करें ? मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि मैं उस राष्ट्रीयकरण को नहीं चाहता हूं जिस के अन्दर अफसर लोग तीन हजार, दो हजार या एक हजार तनख्वाह लें लेकिन पचास हजार की सुविधायें लें । अब राष्ट्रीयकरण जिन कारखानों का हो गया है वे निजी कारखानों की तरह से ही चलते हैं । इसलिए मैंने यहां पर खर्च शब्द का प्रयोग किया है ।

सोमानी जी ने अपने विचार यहां पर आज रखे हैं । आप जानते हैं कि मैं बहुत

अपने ऊपर संयम रखता हूं। मिंक कोट और हीरों वगैरह की चर्चा हुई है । मैं बिल्कुल साफ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। नोकरशाहों में और नगर सेठों में तो सदा सर्वदा का सदियों का शताब्दियों का सम्बन्ध चलता आया है । इसलिए उनको यह बात क्यों नहीं अखरेगी । बड़ी अखरेगी ।

मैंने प्रेरणा की बात भी सुनी है । मुझ को गुस्सा साधारण तौर पर नहीं आता है । लेकिन मैं इसका उत्तर देना चाहता हूं । मोरारजी भाई ने अभी बताया है कि एक लाख आदमी । मान लो बीस लाख आदमी हैं, मेरे पंद्रह सौ के हिसाब से । मैं आज बहुत ही ठंडे दिल से कहना चाहता हूं कि अगर ये बीस लाख आदमी बिल्कुल खत्म हो जाएं, संसार में न रहें, उनकी प्रेरणा से भारत को कोई लाभ न मिले तो भारत कहीं ज्यादा अच्छा हो जाएगा । इन आदमियों की कोई जरूरत नहीं है । ये प्रेरणा की जो बात करते हैं, उनकी जरूरत नहीं है । बीस लाख आदमी अगर खाली पैसा खा कर और खर्च करके ही प्रेरणा पाते हैं तो जितनी जल्दी दुनिया से इनका नामोनिशान मिटे अच्छा है । आखिर हैं तो बीस लाख ही । उस से ज्यादा नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूं कि कभी सोचें जो 50 करोड़ में से बाकी 20 लाख घटाने से बचते हैं 49 करोड़ 80 लाख, उन की प्रेरणा की बात भी तो सोचें । 50 करोड़ की या 49 करोड़ 80 लाख की प्रेरणाओं की बात नहीं सोचते । जो 15सौ या चार सौ या दो सौ या आठ आने या चार आने या दो आने वाले हैं उन की प्रेरणाओं की बात भी तो सोचनी चाहिए । और इसलिए जब हीरों की चर्चा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे घर पर स्वतंत्र वाले भी आये हैं और उन्होंने बताया है, बहुत बढ़िया बात बतायी है कि अपने देश में 8 हजार करोड़ रुपये की तो चांदी जमा है और 4 हजार करोड़ रुपये का सोना जमा है और हीरा कितने का है . . (व्यवधान) . . मैं बताता हूं कि हीरे के साथ जो और चीजें हैं वह मिला कर 15 हजार करोड़ रुपये का माल जमा है । जरा सोचें उस की तरफ । बेमतलब माल जमा हुआ पड़ा है । मैं चाहता हूं कि भारत में विधि और कानून के जरिए ऐसी व्यवस्था और ऐसी संस्था कायम कर दें कि इस पन्द्रह हजार करोड़ रुपये को चांदी के रूप में, सोने के रूप में या हीरे के रूप में . . (व्यवधान) . . अब सोमानी जी अलबत्ता उस हीरे का दूसरा उपयोग करना चाहेंगे, उन के और लोग भी दूसरा उपयोग कर रहे हैं । सुना है 60 हजार डालर यानी चार पांच लाख रुपये खर्च कर के न्युयार्क टाइम्स का स्पेशल सप्लीमेंट निकलवाने में भी उस का उपयोग करते रहते हैं । मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ाया मत करो ? मगर सेठों और नौकरशाहों का यह जमाना अब खत्म हो गया है । . . (व्यवधान) अब देखिए अध्यक्ष महोदय, अब जरा बातें कुछ मजे की आ रही हैं । मैं जल्दी कर रहा हूं ।

अब इसलिए क्योंकि कुछ बातें गलतफहमी पैदा कर सकती हैं, डाक्टर सुशीला नायर वाली बात खास तौर से और औरों ने भी उस को यहां दोहराया है, जैसे कि मैं कोई लोगों को बरखास्त कराना चाहता हूं 20 लाख सरकारी नौकरों को बरखास्त करा देना चाहता हूं । यह बात मैंने नहीं कही थी । मैंने कहा था कि इनको कलम घिस्सु कामों से हटा कर के उपाजऊ कामों में लगाओ चाहे वह खेती के हों, सिंचाई के हों, कारखाने के हों, कलम घिस्सू कामों से हटाओ तो मेहरबानी कर के . . . .

डा० सुशीला नायर : लोहिया साहब, तनख्वाह कैसे बचेगी । आप ने कहा कि सवा सौ के हिसाब से इतने करोड़ बच जायेंगे, वह कैसे बचेंगे ?

डा० राम मनोहर लोहिया : अब तनख्वाह तो बच ही गई । मुश्किल यह है

[डा० राम मनोहर लोहिया]

सुशीला जी, कि उतना आप को समझाने में बहुत ज्यादा वक्त लग जायगा । वह तो बच ही गई । जो गैर-जरूरी फिजुल कलम घिस्सू काम करते रहेंगे तो वह रुपया तो बरबाद जा रहा है और व उपजाऊ काम में लग जायेंगे तो ज्यादा पैदावार होगी । सुशीला जी, आप विजय लक्ष्मी जी के साथ बैठी हुई है, उन से बात कर लीजिए विजय लक्ष्मी जी, आप उन को समझा दें । . . (व्यवधान) . . समझा दिया न ? क्योंकि यह बहुत बड़ी गलतफहमी हो जाती है और मेरा नुकसान वसे भी देश में बहुत होता है । और इसलिए वह जो 3 हजार औरतें निकाली गई हैं मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है और खास तौर से अफसोस इस बात का है कि सब से पहले चक्र औरतों पर चला न कि मर्दों पर ।

डा० सुशीला नायर : सिखाइए उन को जरा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : लोगों ने कहा कि कुछ अपनी सरकारों में कुछ कर के दिखाओ । पहली बात तो यह है कि मेरी सरकार है नहीं । मेरी सरकार तो जब या तो श्री मोरार जी मेरे शिष्य बनें तब होगी या यह लोग वहां पहुंचे । इस के अलावा तो मेरी सरकार होने वाली नहीं है । और क्या तरीका कोई तीसरा बता रहे हो मोरार जी भाई ? नहीं न तो सरकार तो मेरी है नहीं । लेकिन फिर भी मैं आप को बताऊं कि मेरे जितने भी मंत्री हैं जिन पर मेरा थोड़ा भी असर चलता है मैं उन से कहा करता हूं कि पुलिस वाले तुम्हारे साथ चलते हैं, पहरा देते हैं, किसी दूसरी जगह जब तुम जाते हो तो वह तुम को सलामी देते हैं, क्या तुम लंगुर बनना चाहते हो ? यह मैंने कई दफा भाषणों में कहा है और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि हमारे यहां के कई मंत्रियों ने पुलिस का सम्पर्क छोड़ दिया है । मैं कइयों को मोटरों के सम्पर्क से भी थोड़ा बहुत अलग करवा पाया हूं और उस के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी करवायी हैं. . . .

डा० सुशीला नायर : यू०पी० में औरतों को बचाइए . . . (व्यवधान) . . . .

डा० राम मनोहर लोहिया : अब आप कहें तो औरत बन जाऊं और क्या करूं ? (व्यवधान)

एक गलती बड़ी भारी यह हो जाती है कि दो तरह के हिसाब एक साथ चलते रहते हैं । मोरार जी भाई समझते हैं कि एक लाख में से सिर्फ 8 हजार रुपया बचता है । एक लाख के बाद वाली सीढ़ी पर जब आमदनी कर लगता है लेकिन इधर दूसरी तरफ, मैं यहां वालों में से किसी का नाम नहीं लूंगा, वह लोग मुझ को बताते हैं कि कागज के ऊपर तो 8 हजार बचता है लेकिन असलियत में 50 हजार बचता है । आज यहां जितनी गलती हो रही है हिसाब लगाने में उस का कारण यह है कि कभी तो वह 8 हजार वाला हिसाब ले लेते हैं वित्त मंत्री महोदय जो कागज के ऊपर है और कभी वह 50 हजार रुपये वाला हिसाब दूसरे लोग ले लेते हैं जो कि असलियत में है । तो दोनों वस्तुओं से संबंध रखते हो । कागज वाले हिसाब को बिल्कुल खत्म कर दो ।

इस के अलावा मुझे आप से यह कहना है कि कई दफा मुझे ताना मारते हैं स्वतंत्र वाले भी और कम्युनिस्ट वाले भी कि तुम्हारे विचार तो यह हैं लेकिन तुम स्वतंत्र से लेकर के कम्युनिस्ट तक को कैसे इकट्ठा कर रहे हो ? क्यों नहीं इकट्ठा करूं ? और जब कांग्रेस भी हमारे जितनी छोटी रह जायेगी तो कांग्रेस को भी उस के साथ ले लेंगे । मैं नहीं चाहता कि यह विराट विशाल राक्षस अपने साथ ले लूं । वह तो हम लोगों को खा

जायेगा। अगर बराबरी की पार्टियां हो जायंगी तो कांग्रेस से भी मुझ को कोई जाती दुश्मनी नहीं है और यह याद रखना मुझको गुस्सा भी आता है तो खाली एक दिन दो दिन के लिए आता है। उस से ज्यादा नहीं आया करता। तो यह जो सब को इकट्ठा करने वाली बात है आप अच्छी तरह से अध्यक्ष महोदय, समझ चुके हैं कि अगर कोई ऐसी चीज है कि जिस में किसी का साथ मिल सकता है जैसे नौकरशाहों की फिजुलखर्ची में स्वतंत्र का साथ मिल सकता है और जहां बड़े पैसे वाले पूंजीपतियों के संचय में और खर्चे में कम्युनिस्टों का साथ मिल सकता है तो मैं कोशिश क्यों न करूं कि उन दोनों का साथ जब तक हो सके चले। फिर आखिर को तो कहीं नकहीं फैसला हो ही जायेगा। मैदान में चलते चलते पल्टन में नकहीं न कहीं लोग छुट जायेंगे कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर पल्टन चलती रही तो आखिर को अपनी मंजिल पर पहुंच कर के नया हिन्दुस्तान बनाएगी।

Mr. Deputy-Speaker: The question is:

"That this House resolves that the Government should appoint a committee to work out the proposals for restricting individual monthly expenditure to Rs. 1,500 in order that Rs. 1,000 crores may annually be made available for investment in development work.

The Lok Sabha divided:

AYES

Division No. 15] **[16.04 hrs.**

Adichan, Shri P. C.
Anirudhan, Shri K.
Atam Das, Shri
Basi, Shri S. S.
Bhadoria, Shri Arjun Singh
Bhagaban Das, Shri
Bharat Singh, Shri
Bharti, Shri Maharaj Singh
Biswas, Shri J. M.
Chandra Shekhar Singh, Shri
Chaudhuri, Shri Tridib Kumar
Chittybabu, Shri C.
Dar, Shri Abdul Ghani
Desai, Shri C. C.
Devgun, Shri Hardayal
Durairasu, Shri
Fernandes, Shri George
Goel, Shri Shri Chand
Gopalan, Shri P.
Gowda, Shri M. H.
Gupta, Shri Kanwar Lal
Haldar, Shri K.
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri Jagannath Rao
Joshi, Shri S. M.
Kachwai, Shri Hukam Chand
Kamalanathan, Shri
Kandappan, Shri S.
Kapoor, Shri Lakhan Lal
Khan, Shri Ghayoor Ali
Khan, Shri Latafat Ali
Kothari, Shri S. S.
Kripalani, Shri J. B.
Kuchelar, Shri G.
Kundu, Shri S.
Limaye, Shri Madhu
Lohia, Dr. Ram Manohar
Madhukar, Shri K. M.
Meghachandra, Shri M.
Menon, Shri Vishwanatha
Misra, Shri Srinibas
Mohan Swarup, Shri
Molahu Prasad, Shri
Nair, Shri Vasudevan
Nath Pai, Shri
Patel, Shri J. H.
Patil, Shri N. R.
Ram Charan, Shri
Ram Gopal, Shri
Ramamurti, Shri P.
Ramji Ram, Shri
Ray, Shri Rabi
Roy, Shri Chittaranjan
Sambhali, Shri Ishaq
Saminathan, Shri
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Shri Deven
Sharda Nand, Shri
Sharma, Shri Ram Avtar
Sharma, Shri Yogendra
Shastri, Shri Prakash Vir
Shastri, Shri Sheopujan
Sivasankaran, Shri
Sreedharan, Shri A.
Subravelu, Shri
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri P. R.
Tyagi, Shri O. P.
Vajpayee, Shri A. B.
Vidyarthi, Shri R. S.
Viswanatham, Shri Tenneti
Yadav, Shri Ram Sewak

NOES

Agadi, Shri S. A.
Ahirwar, Shri Nathu Ram
Amin, Shri R. K.
Babunath Singh, Shri
Bajpai, Shri Shashi bhushan
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Bhanu Prakash Singh, Shri
Bhargava, Shri B. N.
Bhola Nath, Shri
Birua, Shri Kolai
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chatterji, Shri Krishna Kumar
Chaturvedi, Shri R. L.
Chaudhary, Shri Nitiraj Singh
Chavan, Shri D. R.
Choudhury, Shri J. K.
Dass, Shri C.
Deo, Shri K. P. Singh
Deo, Shri P. K.
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri K. G.
Dhillon, Shri G. S.
Dixit, Shri G. C.
Ering, Shri D.
Girraj Saran Singh, Shri
Gowder, Shri Nanja
Hari Krishna, Shri
Himatsingka, Shri
Jadhav, Shri V. N.
Jena, Shri D. D.
Katham, Shri B. N.
Kedaria, Shri C. M.
Kesri, Shri Sitaram
Khanna, Shri P. K.
Kinder Lal, Shri
Koushik, Shri K. M.
Krishna, Shri M. R.
Kureel, Shri B. N.
Kushok Bakula, Shri
Laskar, Shri N. R.
Lobo Prabhu, Shri
Lutfal Haque, Shri
Mahadeva Prasad, Dr.
Maharaj Singh, Shri
Majhi, Shri M.
Malimariyappa, Shri
Mandal, Shri Yamuna Prasad
Marandi, Shri
Masani, Shri M. R.
Masuriya Din, Shri
Meena, Shri Meetha Lal
Meghrajji, Shri
Menon, Shri Govinda
Minimata, Shrimati Agam Dass Guru
Mishra, Shri Bibhuti
Mody, Shri Piloo
Mohammad Yusuf, Shri
Mohinder Kaur, Shrimati
Mrityunjay Prasad, Shri
Murthy, Shri B. S.
Murti, Shri M. S.
Nageshwar, Shri
Nahata, Shri Amrit
Naidu, Shri Chengalraya
Naik, Shri R. V.
Nayar, Dr. Sushila
Oraon, Shri Kartik
Padmavati Devi, Shrimati
Pahadia, Shri
Pandey, Shri K. N.
Pandey, Shri Vishwa Nath
Pandit, Shrimati Vijaya Lakshmi
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Parmar, Shri D. R.
Partap Singh, Shri
Patil, Shri Deorao
Patil, Shri S. B.
Patodia, Shri D. N.
Pramanik, Shri J. N.
Prasad, Shri Y. A.
Raj Deo Singh, Shri
Ram, Shri T.
Ram Dhan, Shri
Ram Kishan, Shri
Ram Subhag Singh, Dr.
Ram Swarup, Shri
Ramamoorthy, Shri P.
Rana, Shri M. B.
Randhir Singh, Shri
Rane, Shri
Rohatgi, Shrimati Sushila
Roy, Shri Bishwanath
Sambasivam, Shri
Sanghi, Shri N. K.
Sankata Prasad, Dr.
Sarma, Shri A. T.
Sen, Shri P. G.
Sequeira, Shri
Sethuramae, Shri N.
Shah, Shri Manabendra
Sharma, Shri M. R.
Sheo Narain, Shri
Shinkre, Shri
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shivappa, Shri N.
Siddayya, Shri
Singh, Shri D. N.
Singh, Shri D. V.
Solanki, Shri P. N.
Somani, Shri N. K.
Sonavane, Shri
Supakar, Shri Sradhakar
Tamaskar, Shri
Tapuriah, Shri S. K.
Tula Ram, Shri
Uikey, Shri M. G.
Ulaka, Shri Ramachandra
Veerappa, Shri Ramachandra
Verma, Shri Balgovind
Yadav, Shri Chandra Jeet

Mr. Deputy-Speaker: The result of the division is as follows:

Ayes, 73*; Noes, 123†.

The motion was negatived.

The motion is negatived.

---

*AYES: Name of one Member could not be recorded.
†Noes: Name of one Member could not be recorded.